नवसर्जन संस्कृति

RNI No. GJHIN/25/A2786
NAVSARJAN SANSKRUTI

नवसर्जन संस्कृति

अहमदाबाद से प्रकाशित दैनिक

वर्ष : 01
अंक : 019
दि. 19.10.2025,
रविवार
पाना : 04
किंमत : 00.50 पैसा

EDITOR : JIGNESHKUMAR PETHABHAI VAGHELA Regd. Office : B/13, Sneh Plaza Shopping Centre, I.O.C. Road, Chandkheda, Ahmedabad-382 424, Gujarat, India.

Phone : 76983 33307 (M) 84859 51747, 70963 33307 ● Email : navsarjansanskruti2016@gmail.com ● Email : navsarjansanskruti2016@yahoo.com ● Website : www.navsarjansanskruti.com

जीएसटी दरों में कटौती से आम आदमी को बड़ी राहत, मुनाफाखोरों पर होगी सख्त कार्रवाई — वित्त मंत्री सीतारमण ने दी चेतावनी

नई दिल्ली। आम जनता के लिए त्योहारों से पहले राहत की बड़ी खबर आई है। केंद्र सरकार ने घोषणा की है कि जीएसटी की दरों में कटौती का लाभ अब सीधे उपभोक्ताओं तक पहुंचना चाहिए, अन्यथा जो व्यापारी या कंपनियां ऐसा नहीं करेंगे, उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने शनिवार को बताया कि 22 सितंबर से लागू हुई नई जीएसटी दरों के बाद रोजमर्रा की जरूरतों से जुड़ी 54 वस्तुओं के दामों में 6 से 12 प्रतिशत तक की कमी आई है। इनमें बटर, घी, टूथब्रश, शैंपू, छाता, बच्चों के खिलौने जैसी रोजमर्रा की वस्तुएं शामिल हैं। वित्त मंत्रालय ने यह दावा देशभर के विभिन्न जोनों से मिली रिपोर्टों के आधार पर किया है।

सीतारमण ने कहा कि सरकार चाहती है कि टैक्स में हुई इस कटौती का सीधा लाभ जनता तक पहुंचे। लेकिन यदि कोई व्यापारी इस लाभ को रोकता है या मुनाफाखोरी करता है, तो उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने स्पष्ट कहा कि ऐसे लोगों को सजा दिलाने के प्रावधान किए जा रहे हैं। वित्त मंत्री ने यह भी बताया कि जीएसटी कटौती के बाद उपभोक्ताओं से काफी शिकायतें आई हैं। उपभोक्ता मंत्रालय के पास आई शिकायतों में से अब तक 3075 मामलों को जांच के लिए अप्रत्यक्ष कर विभाग को भेजा गया है और संबंधित अधिकारी इन पर जांच कर रहे हैं।

सरकार ने जनता से अपील की है

कि अगर किसी वस्तु पर जीएसटी की दर कम हुई है, लेकिन दुकानदार या कंपनी ने उसका दाम नहीं घटाया है, तो इसकी शिकायत उपभोक्ता मंत्रालय में करें। इस मौके पर वित्त मंत्री के साथ मंच पर वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल तथा इलेक्ट्रॉनिक्स व सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री अश्विनी वैष्णव भी मौजूद थे। तीनों मंत्रियों ने संयुक्त रूप से बताया कि नवरात्र से शुरू हुए "जीएसटी बचत उत्सव" का उद्देश्य जनता को टैक्स कटौती का प्रत्यक्ष लाभ पहुंचाना है।

वित्त मंत्री सीतारमण ने कांग्रेस पर निशाना साधते हुए कहा कि विपक्ष इसे "भूल सुधार" कह रहा है, जबकि वास्तव में यह भूल सुधार नहीं, बल्कि अर्थव्यवस्था को प्रोत्साहित करने की नीति है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस ने कभी जीएसटी को लागू करने का साहस नहीं किया, जबकि मोदी सरकार ने इसे न सिर्फ लागू किया, बल्कि लगातार इसे आम जनता के हित में सरल और न्यायसंगत बनाया। सीतारमण ने बताया कि सरकार का मासिक जीएसटी संग्रह पहले से ही दो लाख करोड़ रुपये के पार जा रहा है, इसलिए टैक्स कटौती से जनता को राहत देने की गुंजाइश बनी। इससे खपत में वृद्धि होगी, जिससे न केवल बाजारों में मांग बढ़ेगी, बल्कि उत्पादन और रोजगार में भी वृद्धि होगी।

वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल ने कहा कि इस वर्ष सरकार ने पहले इनकम टैक्स में राहत दी और अब जीएसटी में कटौती की है, जिससे अर्थव्यवस्था को कई सकारात्मक परिणाम मिलेंगे। उन्होंने बताया कि अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष (आईएमएफ) ने भारत की विकास दर के अनुमान को बढ़ाकर 6.6 प्रतिशत कर दिया है, जो इस नीति की सफलता को दर्शाता है। गोयल ने कहा कि भारत में स्वदेशी उत्पादन की भावना बढ़ी है, जिससे निर्यात में भी लगातार वृद्धि हो रही है। इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि जीएसटी की दरों में कमी के बाद इलेक्ट्रॉनिक्स बाजार में जबरदस्त उछाल देखा गया है। मोबाइल फोन, टीवी, एसी जैसे उपकरणों की बिक्री में 20 से 25 प्रतिशत तक की वृद्धि हुई है। उन्होंने बताया कि इस बढ़ती मांग का असर सीधे-सीधे रोजगार पर पड़ रहा है। इलेक्ट्रॉनिक्स निर्माण क्षेत्र में पहले से ही करीब 25 लाख लोगों को प्रत्यक्ष रोजगार मिला हुआ है और अब नए निवेश और उत्पादन बढ़ने के साथ रोजगार के और अवसर पैदा हो रहे हैं।

सरकार का मानना है कि यह कदम आम आदमी की जेब को सीधी राहत देगा, साथ ही देश की अर्थव्यवस्था में नई ऊर्जा का संचार करेगा। विशेषज्ञों के अनुसार, टैक्स दरों में कटौती से न केवल उपभोक्ताओं की क्रय शक्ति बढ़ेगी बल्कि बाजारों में मांग का चक्र भी तेज होगा। इससे देश के मैन्यूफैक्चरिंग और सर्विस सेक्टर दोनों को गति मिलेगी।

त्योहारी सीजन में जब बाजारों में खरीदारी का माहौल है, सरकार का यह कदम उपभोक्ताओं के लिए एक बड़ी राहत बनकर आया है। वित्त मंत्रालय का कहना है कि अब जरूरी है कि व्यापारी और कंपनियां ईमानदारी से इस लाभ को जनता तक पहुंचाएं ताकि जीएसटी दरों में कटौती का वास्तविक उद्देश्य — "जनता को राहत, बाजार को गति और अर्थव्यवस्था को मजबूती" — पूरी तरह साकार हो सके।

पीओके में सियासी भूकंप: प्रधानमंत्री हक पर शरणार्थियों की उपेक्षा का आरोप, तीन वरिष्ठ मंत्रियों ने एक साथ दिया इस्तीफा

इस्लामाबाद/मीरपुर। पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू-कश्मीर (पीओके) में राजनीतिक संकट गहराता जा रहा है। प्रधानमंत्री चौधरी अनवारुल हक की सरकार से तीन वरिष्ठ मंत्रियों ने एक साथ इस्तीफा देकर वहां की सत्ता को हिला दिया है। इस्तीफा देने वाले मंत्रियों ने हक पर शरणार्थियों और पीओके के निवासियों के अधिकारों की खुली उपेक्षा का आरोप लगाते हुए कहा कि मौजूदा सरकार ने अपनी नैतिक और राजनीतिक वैधता खो दी है। बताया गया है कि सूचना मंत्री पीर मजहर सईद पहले ही पद छोड़ चुके हैं, और अब वित्त मंत्री अब्दुल मजीद खान, खाद्य मंत्री चौधरी अकबर इब्राहिम तथा मंत्री असीम शरीफ भट ने भी अपने इस्तीफे की घोषणा कर दी है। यह घटनाक्रम ऐसे समय हुआ है जब पीओके में हाल के महीनों से राजनीतिक अस्थिरता, प्रशासनिक विफलता और जनता के बढ़ते आक्रोश ने माहौल को अस्थिर बना रखा है।

पाकिस्तानी अख़बार द एक्सप्रेस ट्रिब्यून की रिपोर्ट के मुताबिक, इस्तीफा देने वाले मंत्रियों ने आरोप लगाया है कि प्रधानमंत्री हक न केवल राजनीतिक रूप से कमजोर हो गए हैं, बल्कि उन्होंने पीओके के लाखों निवासियों और पाकिस्तान में रह रहे करीब 25 लाख

कश्मीरी शरणार्थियों के संवैधानिक व राजनीतिक अधिकारों की खुली अनदेखी की है। मंत्रियों ने कहा कि सरकार की नीतियां क्षेत्र के लोगों की उम्मीदों और आकांक्षाओं के बिल्कुल विपरीत हैं, जिसके चलते जनता का भरोसा उठ गया है।

वित्त मंत्री अब्दुल मजीद खान ने अपने त्यागपत्र में कहा कि उनका विरोध प्रधानमंत्री हक की "निष्क्रियता और नीतिगत विफलता" के खिलाफ है। उन्होंने लिखा कि वे पाकिस्तान में विलय की विचारधारा के समर्थक हैं, लेकिन मौजूदा सरकार शरणार्थियों के अधिकारों की रक्षा में पूरी तरह असफल रही है। खान ने जम्मू-कश्मीर संयुक्त कार्रवाई समिति (JAAC) की भी तीखी आलोचना की, जिसने हाल ही में पीओके विधानसभा में शरणार्थियों के लिए आरक्षित 12 सीटों को समाप्त करने की मांग की थी। उन्होंने इस प्रस्ताव को "विभाजनकारी, अवसरवादी और गैर-लोकतांत्रिक" करार दिया।

खान ने कहा कि JAAC और संघीय प्रतिनिधियों के बीच जिस समझौते का हवाला दिया जा रहा है, उसमें किसी तरह की पारदर्शिता या आम सहमति नहीं थी। उन्होंने कहा कि इस फैसले से हजारों विस्थापित कश्मीरी शरणार्थियों के अधिकार खतरे में पड़ गए हैं, जिन्होंने दशकों से पाकिस्तान के लिए अपने घर और पहचान की कुर्बानी दी है। खान ने राष्ट्रपति आसिफ अली जरदारी, प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ और सेना प्रमुख जनरल असीम मुनीर को पत्र लिखकर इस मामले में तत्काल हस्तक्षेप की मांग की है।

खाद्य मंत्री चौधरी अकबर इब्राहिम ने भी प्रधानमंत्री हक के खिलाफ गंभीर आरोप लगाए। उन्होंने कहा कि शरणार्थी केवल "राजनीतिक संख्या" नहीं हैं, बल्कि वे वे लोग हैं जिन्होंने पाकिस्तान के लिए दशकों तक पीड़ा सही है। इब्राहिम ने कहा कि हक सरकार ने इन शरणार्थियों की संवैधानिक स्थिति की रक्षा करने में पूरी तरह असफलता दिखाई है और ऐसे नेतृत्व में रहना अब "नैतिक रूप से असंभव" हो गया है।

मंत्री असीम शरीफ भट ने अपने इस्तीफे में लिखा कि हक सरकार ने जनता के विश्वास को धोखा दिया है और प्रशासनिक नाकामी की हद पार कर दी है।

राजनाथ सिंह की दो-टूक चेतावनी: पाकिस्तान की हर इंच ज़मीन अब ब्रह्मोस की जद में, बोले – ऑपरेशन सिंदूर तो बस एक ट्रेलर था

लखनऊ। देश की सुरक्षा क्षमता और आत्मनिर्भर रक्षा उत्पादन की दिशा में एक और ऐतिहासिक उपलब्धि दर्ज करते हुए रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने शनिवार को कहा कि भारत की सैन्य ताकत अब उस मुकाम पर पहुंच चुकी है जहां जीत हमारी आदत बन गई है। लखनऊ में आयोजित एक विशाल जनसभा में बोलते हुए राजनाथ सिंह ने "ऑपरेशन सिंदूर" की सफलता की सराहना करते हुए कहा कि यह अभियान भारत की रणनीतिक और तकनीकी क्षमता का जीवंत प्रमाण है। उन्होंने कहा, "ऑपरेशन सिंदूर ने साबित कर दिया है कि जीत अब हमारे लिए कोई अपवाद नहीं, बल्कि एक परंपरा बन चुकी है। हमने यह दुनिया को दिखा दिया है कि भारत अब किसी भी चुनौती का जवाब देने में सक्षम है।"

रक्षा मंत्री ने यह भी स्पष्ट कहा कि ब्रह्मोस सुपरसोनिक मिसाइल प्रणाली की पहुंच अब इतनी विस्तृत और सटीक हो चुकी है कि पाकिस्तान का कोई भी कोना इससे बाहर नहीं है। उन्होंने मंच से दो-टूक शब्दों में कहा, "पाकिस्तान की हर इंच ज़मीन अब हमारे ब्रह्मोस की जद में है।

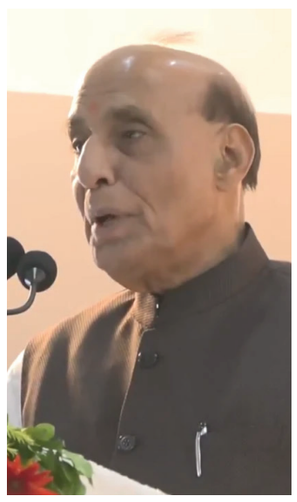

दुश्मनों को यह समझ लेना चाहिए कि भारत अब केवल चेतावनी नहीं देता, बल्कि कार्रवाई भी करता है। ऑपरेशन सिंदूर में जो हुआ, वह तो बस एक ट्रेलर था।"

लखनऊ के सरोजिनी नगर स्थित ब्रह्मोस एयरोस्पेस यूनिट में निर्मित मिसाइलों की पहली खेप को राजनाथ सिंह और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने हरी झंडी दिखाई। यह यूनिट देश में रक्षा उत्पादन के स्वदेशी अभियान "मेक इन इंडिया" की सबसे बड़ी मिसाइल परियोजनाओं में से एक है। इस अवसर पर ब्रह्मोस एयरोस्पेस ने बताया कि यहां से मिसाइल प्रणाली की पहली खेप का सफल एकीकरण और परीक्षण पूरा कर लिया गया है। राजनाथ सिंह ने सशस्त्र बलों की सटीकता और तत्परता की प्रशंसा करते हुए कहा कि आज भारत की मिसाइल क्षमता इस स्तर पर पहुंच चुकी है कि कोई भी दुश्मन देश की सीमाओं को चुनौती नहीं दे सकता। उन्होंने कहा, "हमारे सैनिक केवल सरहद की रक्षा नहीं करते, बल्कि भारत के आत्मविश्वास और स्वाभिमान की भी रक्षा करते हैं। देश को अब यह भरोसा हो गया है कि हमारे दुश्मन ब्रह्मोस से नहीं बच पाएंगे।"

रक्षा मंत्री ने अपने भाषण में यह भी बताया कि मिसाइल निर्माण जैसी परियोजनाओं से देश की अर्थव्यवस्था को भी मजबूती मिल रही है। उन्होंने कहा, "हर मिसाइल केवल रक्षा का प्रतीक नहीं, बल्कि विकास का साधन भी है। मिसाइल निर्माण से मिलने वाले टैक्स से सरकार स्कूल बना सकती है, अस्पताल खड़े कर सकती है और ऐसी योजनाएं चला सकती है जो आम आदमी की जिंदगी को बेहतर बनाती हैं। ब्रह्मोस केवल हथियार नहीं, बल्कि यह हमारे बच्चों की शिक्षा, हमारे परिवारों की सेहत और पूरे समाज के लिए अवसर का प्रतीक है।"

उन्होंने कहा कि आने वाले वर्षों में भारत की रक्षा उद्योग और नागरिक अर्थव्यवस्था के बीच यह 'synergy' और मजबूत होगी। ब्रह्मोस जैसी परियोजनाएं न केवल सैन्य शक्ति को बढ़ाएंगी, बल्कि लाखों युवाओं को रोजगार भी प्रदान करेंगी। उन्होंने कहा, "यह मिसाइल सिर्फ हमारे सैनिकों की ताकत नहीं, बल्कि करोड़ों भारतीयों की आकांक्षाओं का प्रतीक है। यह इस बात का प्रमाण है कि 'मेड इन इंडिया' अब केवल एक नारा नहीं, बल्कि एक वैश्विक ब्रांड बन चुका है, जिसे पूरी दुनिया सम्मान की दृष्टि से देख रही है।"

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इस मौके पर कहा कि उत्तर प्रदेश अब केवल कृषि और संस्कृति का प्रदेश नहीं रहा, बल्कि यह रक्षा उत्पादन का केंद्र बन चुका है। उन्होंने बताया कि लखनऊ, कानपुर, अलीगढ़ और झांसी जैसे शहर अब रक्षा उद्योग में अग्रणी भूमिका निभा रहे हैं।

कार्यक्रम के अंत में राजनाथ सिंह ने सभी वैज्ञानिकों, इंजीनियरों और तकनीशियनों को बधाई देते हुए कहा कि यह उपलब्धि भारत के आत्मनिर्भरता के उस संकल्प का प्रतीक है, जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में साकार हो रहा है। उन्होंने कहा कि अब भारत किसी पर निर्भर नहीं है — हम अपने रक्षा उपकरण खुद बनाते हैं, खुद डिजाइन करते हैं और जरूरत पड़ने पर उनका इस्तेमाल करने का साहस भी रखते हैं।

लखनऊ की धरती से उठी यह घोषणा केवल एक भाषण नहीं थी, बल्कि एक सशक्त संदेश था — कि भारत अब नई सोच, नई तकनीक और नए आत्मविश्वास के साथ आगे बढ़ रहा है। और जो "ऑपरेशन सिंदूर" में दिखा, वह वाकई सिर्फ़ एक ट्रेलर था — आने वाले समय में पूरी दुनिया भारत की असली ताकत देखेगी।

भारत-चीन रिश्तों में नई उड़ान: शंघाई से दिल्ली के बीच ईस्टर्न एयरलाइंस की फ्लाइट नौ नवंबर से फिर शुरू

बीजिंग। भारत और चीन के बीच लंबे समय से जमी बर्फ अब धीरे-धीरे पिघलती नजर आ रही है। दोनों देशों के बीच कूटनीतिक और आर्थिक संबंधों में सुधार के संकेत मिल रहे हैं। इसी क्रम में चाइना ईस्टर्न एयरलाइंस ने शंघाई और नई दिल्ली के बीच सीधी उड़ानें दोबारा शुरू करने की घोषणा की है। यह सेवा नौ नवंबर से प्रारंभ होगी, जो पांच साल के अंतराल के बाद दोनों देशों के बीच शुरू होने वाली सबसे अहम हवाई कड़ी मानी जा रही है। एयरलाइन की ओर से जारी बयान के मुताबिक, शंघाई–दिल्ली राउंड ट्रिप फ्लाइट हर बुधवार, शनिवार और रविवार को संचालित की जाएगी। शंघाई के पुडोंग अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे से उड़ान दोपहर 12:50 बजे रवाना होगी और नई दिल्ली के इंदिरा गांधी अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे पर शाम 5:45 बजे पहुंचेगी। वहीं, वापसी की उड़ान दिल्ली से शाम 7:55 बजे प्रस्थान करेगी और अगले दिन सुबह 4:10 बजे शंघाई पुडोंग एयरपोर्ट पर उतरेगी।

इस रूट के लिए टिकटों की बिक्री पहले ही शुरू हो चुकी है और शुरुआती चरण में यात्रियों की मांग को देखते हुए सीटें तेजी से बुक हो रही हैं। विमानन विशेषज्ञों के मुताबिक, यह उड़ान न केवल व्यापारिक और पर्यटक यात्रियों के लिए राहत लेकर आएगी, बल्कि दोनों देशों के बीच प्रत्यक्ष कनेक्टिविटी बहाल करने की दिशा में भी बड़ा कदम है।

गौरतलब है कि इस साल अगस्त में चीन के तियानजिन में आयोजित शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गनाइजेशन (SCO) समिट के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग के बीच हुई मुलाकात में द्विपक्षीय संवाद बहाल करने और हवाई संपर्कों को फिर से शुरू करने पर सहमति बनी थी।

सेहत पर खतरा: अल्ट्रा-प्रोसेस्ड फूड बन रहे हैं नये जमाने का धीमा जहर

वॉशिंगटन। आज की व्यस्त जीवनशैली में पैक्ड स्नैक्स, इंस्टेंट नूडल्स, बर्गर और चिप्स जैसे अल्ट्रा-प्रोसेस्ड फूड हमारी रोजमर्रा की डाइट का अभिन्न हिस्सा बन चुके हैं। हालांकि, फ्लोरिडा अटलांटिक यूनिवर्सिटी (FAU) के हालिया अध्ययन ने चेतावनी दी है कि ये खाद्य पदार्थ धीरे-धीरे धूम्रपान जितने ही खतरनाक साबित हो रहे हैं। शोधकर्ताओं के अनुसार, अल्ट्रा-प्रोसेस्ड फूड शरीर में सूजन बढ़ाता है, जिससे हृदय रोग, कैंसर और मानसिक बीमारियों का खतरा कई गुना बढ़ जाता है। विशेषज्ञों ने इसे "फूड इंडस्ट्री का तंबाकू संकट" भी बताया है।

अल्ट्रा-प्रोसेस्ड फूड वे पदार्थ हैं जिन्हें लंबे समय तक टिकाऊ, स्वादिष्ट और आकर्षक बनाए रखने के लिए कृत्रिम रंग, फ्लेवर, एडिटिव्स और प्रिजर्वेटिव्स मिलाए जाते हैं। इनमें पोषण बहुत कम और नमक, चीनी तथा अस्वस्थ वसा की मात्रा अत्यधिक होती है। सॉफ्ट ड्रिंक्स, बर्गर, बिस्किट, सॉसेज, पैकेट वाले स्नैक्स, प्रोसेस्ड मीट और पैकेज्ड जूस इसी श्रेणी में आते हैं। सुविधाजनक होने के बावजूद ये फूड स्वास्थ्य के लिए हानिकारक हैं।

अमेरिका में वयस्कों के खानपान का लगभग 60% और बच्चों का 70% हिस्सा अल्ट्रा-प्रोसेस्ड फूड से आता है। FAU के अध्ययन में 9,254 वयस्कों के खानपान का विश्लेषण किया गया। शोध में पाया गया कि जिन लोगों की कुल कैलोरी का 60 से 79% हिस्सा ऐसे फूड से आता

है, उनके शरीर में हाई-सेंसिटिव सी-रिएक्टिव प्रोटीन (hs-CRP) का स्तर सबसे अधिक पाया गया। यह प्रोटीन शरीर में सूजन का मुख्य संकेतक है, जो हृदय रोग, कैंसर और मेटाबॉलिक डिजीज का कारण बन सकता है।

अध्ययन से यह भी पता चला है कि अल्ट्रा-प्रोसेस्ड फूड का अत्यधिक सेवन न केवल हृदय रोगों से जुड़ा है, बल्कि कैंसर और मानसिक बीमारियों से भी इसका गहरा संबंध है। अमेरिका में युवाओं के बीच कोलोरेक्टल (आंत के) कैंसर के मामलों में तेजी से वृद्धि हो रही है, जो इन फूड्स की बढ़ती खपत से जुड़ी हो सकती है। इसके अलावा, ऐसे फूड का सेवन डिप्रेशन, एंग्जायटी और अन्य मानसिक विकारों के खतरे को भी बढ़ाता है।

नीति विशेषज्ञों का कहना है कि जिस तरह कभी तंबाकू उद्योग ने सार्वजनिक स्वास्थ्य को गंभीर खतरे में डाला था, अब वैसा ही प्रभाव फूड इंडस्ट्री का दिखाई दे रहा है। नुकसान के प्रमाण लगातार बढ़ रहे हैं, लेकिन नीतिगत बदलाव बहुत धीमी गति से हो रहे हैं। विशेषज्ञों ने सुझाव दिया है कि खाद्य उत्पादों की लेबलिंग में पारदर्शिता लाई जाए, हानिकारक एडिटिव्स और रंगों पर सख्त नियंत्रण लगाया जाए, और स्कूलों व सार्वजनिक संस्थानों में स्वस्थ भोजन विकल्पों को बढ़ावा दिया जाए।

शोधकर्ता और चिकित्सक चेतावनी दे रहे हैं कि अगर यह प्रवृत्ति जारी रही, तो आने वाले वर्षों में हृदय रोग, कैंसर और मानसिक रोगों के मामले और बढ़ सकते हैं। उन्होंने आम लोगों को भी अलर्ट किया है कि त्वरित और पैकेज्ड भोजन पर निर्भरता को कम करें और प्राकृतिक, ताजगी से भरपूर आहार को प्राथमिकता दें। अल्ट्रा-प्रोसेस्ड फूड भले सुविधाजनक हों, लेकिन धीरे-धीरे ये हमारी सेहत पर गंभीर चोट पहुँचाने वाला "धीमा जहर" बनते जा रहे हैं।

संपादकीय

न पटाखों के साथ संयम भी जरूरी

दिवाली मनाने के उत्साही लोगों की आकांक्षाओं के अनुरूप सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली और एनसीआर में कुछ शर्तों के साथ ग्रीन पटाखे जलाने की अनुमति दे दी है। इसके बावजूद स्वच्छ हवा बनाए रखने व प्रदूषण नियंत्रण के लिए हमारे संयम व जिम्मेदार व्यवहार की जरूरत होगी। यह तथ्य किसी से छिपा नहीं है कि हमारी राष्ट्रीय राजधानी दुनिया की सबसे प्रदूषित राजधानियों में शुमार है। दुनिया के बीस शीर्ष प्रदूषित शहरों में करीब आधे भारत में हैं। पर्व, आस्था व विश्वास अपनी जगह हैं, लेकिन प्राणवायु का स्वच्छ रहना लाखों लोगों के जीवन का प्रश्न भी है। यही वजह है कि दिल्ली-एनसीआर में कुछ शर्तों के साथ दीपावली पर ग्रीन पटाखों की अनुमति देते वक्त सुप्रीम कोर्ट ने संतुलित दृष्टिकोण अपनाने की नसीहत दी है, जिससे हमारी आस्था का सम्मान हो सके और पर्यावरण की रक्षा भी हो। निस्संदेह, कोर्ट के फैसले से वे लोग उत्साहित होंगे, जो ग्रीन पटाखे चलाने की अनुमति चाहते थे। लेकिन इसका एक पक्ष यह भी है कि पर्यावरण संरक्षण से जुड़े लोग इससे निराश हो सकते हैं। पर्यावरण प्रेमियों की चिंता वाजिब है। अक्सर देखा जाता है कि ग्रीन पटाखे जलाने वालों पर नियामक एजेंसियां निगरानी नहीं रख पाती हैं। चिंता की बात यह भी है कि ग्रीन पटाखों के नाम पर घातक पटाखे भी जलाए जा सकते हैं। विगत के अनुभव बताते हैं कि अदालती रोक के बावजूद त्योहार पर जमकर आतिशबाजी हुई थी। दरअसल, कुछ लोगों की दलील थी कि पर्व विशेष पर ही प्रदूषण के नाम पर रोक लगाई जाती है, जिससे त्योहार का रंग फीका हो जाता है। कुछ लोगों ने इसे प्रतिष्ठा का प्रश्न भी बना लिया। लेकिन सवाल यह है कि यह कैसे सुनिश्चित हो पाएगा कि ग्रीन पटाखों की आड़ में घातक पटाखे नहीं बेचे जा सकें। हमारी निगरानी करने वाली एजेंसियों व विभागों की कारगुजारियों पर अक्सर सवालिया निशान लगाए जाते हैं।

वैसे एक हकीकत यह भी है कि हर गली-मोहल्ले की दुकानों में प्रदूषण फैलाने वाले पटाखों की निगरानी कर पाना व्यावहारिक भी नहीं है। इस बात को लेकर अक्सर बहस होती रही है कि परंपरागत रूप से दिवाली में पटाखों की अनिवार्यता नहीं रही है। निस्संदेह, दीप पर्व उजाले का उत्सव है, ताकि धरा पर कहीं अंधेरा न रह जाए, गरीब की झोपड़ी भी रोशन हो, समृद्धि हर घर तक पहुंचे। सही मायनों में पर्व सामूहिकता की भावना पर केंद्रित होते हैं। ऐसे में यदि हम घातक पटाखे जलाकर श्वास रोगों से पीड़ित मरीजों से लेकर आम आदमी को मुश्किल में डाल दें, तो यह पर्व का मर्म नहीं कहा जा सकता। वैसे ग्रीन पटाखों के बारे में भी निश्चित रूप से नहीं कहा जा सकता कि उनके उत्पादन के दौरान निर्धारित मानकों का पालन किया गया हो। पटाखे जिस गुणवत्ता से बनते और बिकते हैं, कहना मुश्किल ही है कि वे वास्तव में पर्यावरण के अनुकूल होंगे। वैसे यह भी हकीकत है कि दिल्ली में हर साल ठंड की दस्तक के साथ बढ़ने वाले घातक प्रदूषण के लिए सिर्फ पटाखे ही जिम्मेदार नहीं होते। मौसम की प्रतिकूलता तथा जनसंख्या के बढ़ते घनत्व के कारण महानगरों में बहुमंजिला इमारतों के विस्तार से भी हवा का प्राकृतिक प्रवाह बाधित होता है, जिसके चलते प्रदूषण की परत दिल्ली, राष्ट्रीय राजधानी और निकटवर्ती शहरों के ऊपर छाई रहती है। निस्संदेह, पर्यावरण संरक्षण से जुड़े कार्यकर्ताओं के साथ-साथ आम नागरिकों को भी पटाखों के सीमित व संयमित उपयोग के बारे में गंभीरता से विचार करना चाहिए। बहरहाल, सुप्रीम कोर्ट के दिल्ली व एनसीआर में ग्रीन पटाखे चलाने की अनुमति देने के फैसले के आलोक में कहा जा सकता है कि शेष देश में भी प्रदूषण रोकने के लिए गंभीर पहल की जानी चाहिए। देश के कई अन्य बड़े शहर दुनिया के सबसे प्रदूषित शहरों की सूची में दर्ज हैं। वहीं दूसरी ओर केवल सर्दियों में ही प्रदूषण नियंत्रण की पहल नहीं की जानी चाहिए। यह साल भर निरंतर चलने वाली प्रक्रिया बननी चाहिए। इसके अलावा जरूरी है कि प्रदूषण फैलाने वाले अन्य कारकों पर नियंत्रण किया जाए। हम अक्सर पटाखे व पराली जलाने पर जिम्मेदारी डालकर अन्य प्रदूषण के कारकों को नजरअंदाज कर देते हैं।

बिहार की नई राजनीतिक करवट से विकास और सुरक्षा की मिलेगी गारंटी

> बिहार के लोगों को यह भी पता है कि उनके पड़ोसी राज्य पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी, झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जिन अल्पसंख्यकों की राजनीति कर रहे हैं, उससे बंगलादेश का षड्यंत्र सफल हो या न हो, लेकिन पूर्वी भारत निकट भविष्य में रक्तरंजित भी हो सकता है।

बिहार विधानसभा चुनाव 2025, कई मायने में राष्ट्रीय और सूबाई राजनीति को प्रभावित करेगा, क्योंकि 2026 में पश्चिम बंगाल और 2027 में उत्तरप्रदेश में भी विधान सभा चुनाव होने हैं। यही नहीं, पूर्वी भारत की सुरक्षा को भी यह चुनाव सुनिश्चित करेगा। इस चुनाव में भाजपा के नेतृत्व वाले एनडीए की रीति-नीति, कांग्रेस के नेतृत्व वाले इंडिया गठबंधन का अंतर्कलह और मशहूर चुनावी रणनीतिकार प्रशांत किशोर की नवस्थापित पार्टी जनसुराज द्वारा उठाए हुए मुद्दे गहरा असर डालेंगे। वहीं, एआईएमआईएम और अन्य छुटभैये दलों की कोशिशें मतदाताओं के मनोमिजाज पर क्या रंग जमाएंगी और अपने साइलेंट मतदान ट्रेंड से वो क्या गुल खिलाएंगे, इसका पता तो 14 नवंबर को ही पता लग पायेगा, क्योंकि राजनीतिक रूप से यह प्रदेश बहुत ही जागरूक प्रदेश है। महंगाई और बेरोजगारी से जूझ रहे आम बिहारियों के दिल मे अब सामाजिक न्याय से भी ज्यादा हिंदुत्व की लहरें उफान मार रही हैं। क्योंकि उन्हें पता है कि इस्लामिक देशों और चीन-अमेरिका के सहयोग से बनने वाले 'ग्रेटर बंगलादेश' से शांतिप्रिय बिहार भविष्य में गुजरात, राजस्थान, पंजाब और जम्मूकश्मीर की तरह ही युद्ध भूमि भी बन सकता है।

बिहार के लोगों को यह भी पता है कि उनके पड़ोसी राज्य पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी, झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जिन अल्पसंख्यकों की राजनीति कर रहे हैं, उससे बंगलादेश का षड्यंत्र सफल हो या न हो, लेकिन पूर्वी भारत निकट भविष्य में रक्तरंजित भी हो सकता है। इसलिए विकसित, समृद्ध और ज्ञान की संस्कृति की रक्षा के लिए बिहार वासी कुछ ठोस व कड़ा निर्णय भी ले सकते हैं। उन्हें पता है कि इंडिया गठबंधन के राजद, कांग्रेस, भाकपा माले, वीआईपी, वामपंथी दलों की विचारधारा भी पाकिस्तान-बंगलादेश की सरकारों से काफी मिलती जुलती है। इसलिए यदि इन्हें नहीं रोका गया तो संभव है कि भविष्य में ये लोग बिहार को भी उसमें शामिल करवा दें। ऐसा इसलिए कि टीवी स्क्रीन और सोशल मीडिया पर इंडिया गठबंधन के नेताओं के जो हिन्दू विरोधी बयान और कार्यप्रणाली सामने आती रहती है, इससे बिहार के मतदाता अपने राज्य के भविष्य को लेकर चिंतित रहते हैं। बीते वर्षों में उन्होंने महसूस किया है कि राज्य में जंगलराज (2000-2005) का पर्याय बन चुका राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद का कुनबा और उनके सरदार तेजस्वी यादव, पूर्व उपमुख्यमंत्री जनता दल यूनाइटेड के नेता व मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के सहयोग से ब्रेक के बाद सत्ता में आ जाते हैं, इसलिए इसबार ऐसा रणनीतिक मतदान किया जाए कि ऐसी किसी सियासी बात की संभावना भी नहीं बचे।

बिहार से जुड़े सूत्र बताते हैं कि सूबे में भाजपा के अलावा जनसुराज का प्रदर्शन अच्छा हो सकता है, क्योंकि लालू प्रसाद और नीतीश कुमार की कारगुजारियों से प्रबुद्ध बिहारी बहुत ही नाराज चल रहे हैं और ग्राम स्तर पर वह नए बिहार का निर्माण करने के लिए एक मुहिम चला रहे हैं। यह गैर धार्मिक और गैर जातीय मुहिम है, जिसका मकसद बिहार के विकास और किसी भी अंतरराष्ट्रीय षड्यंत्र से बिहार की सुरक्षा की बात उनके एजेंडे में है। यही वजह है कि राष्ट्रवादी भाजपा और उसके सहयोगियों के अलावा जनसुराज के प्रत्याशियों की ओर वे करवट ले रहे हैं।

राजनीतिक विश्लेषकों का भी मानना है कि आपसी दांवपेंच से परेशान एनडीए के नेताओं और बिखरे या कई सीटों पर आपस में ही नूराकुश्ती करने वाले इंडिया गठबंधन के नेताओं के अलावा जो नया विकल्प मौजूद है, उसे ही इस बात मजबूत विपक्ष की जिम्मेदारी मिलने लायक जनसमर्थन दे दिया जाए, इससे राष्ट्रवादी सरकार के बनने और जनहित के मुद्दे पर उसे सक्रिय करने की गारंटी मिल जाएगी। इसलिए सच कहूं तो राजनीतिक अहंकार और बुद्धिजीवियों की बिखरी टंकार के बीच बिहार विधानसभा चुनाव 2025 की चुनावी लड़ाई दिलचस्प होने जा रही है।

जैसे-जैसे चुनाव प्रचार जोर पकड़ेगा, बुद्धिजीवियों की निर्दलीय और सर्वदलीय राजनीतिक मुहिम तेज होती जाएगी। सीट बंटवारे में जो कलह दिखाई दी, उसके पीछे भी इन्हीं बुद्धिजीवियों के हाथ की खबरें हैं। खासकर कांग्रेस के लिए नई राजनीतिक जमीन तैयार करने वाले बुद्धिजीवी तो इस बात पर अड़े हुए हैं कि किसी भी कीमत पर अपने दूरगामी राजनीतिक हितों से समझौता नहीं करना है। इससे स्पष्ट है कि यूपी में जो गलती 2022 के विधानसभा चुनाव में अखिलेश यादव किये थे, 2025 में वही गलती दुहराकर तेजस्वी यादव भी सियासी रूप से अप्रासंगिक हो जाएंगे। स्पष्ट है कि बिहार की नई राजनीतिक करवट से विकास और सुरक्षा दोनों की गारंटी मिलेगी।

प्रेरणा

मीरा का टूटा सितार और हृदय का अमर राग

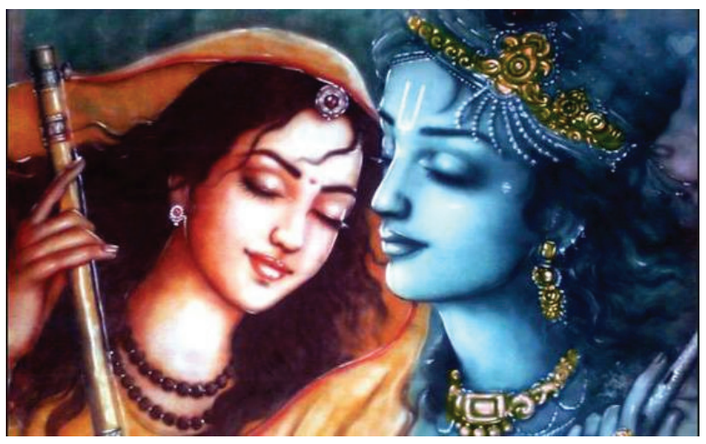

चित्तौड़ के राजमहल में रात का समय था। दीपों की लौ मंद पड़ चुकी थी, और कक्ष के कोने में एक दीया अभी भी टिमटिमा रहा था। वही दीया जिसकी मद्धिम लौ के सामने मीरा बाई अपने प्रियतम श्रीकृष्ण का नाम जप रही थीं। उनके हाथों में वह पुराना सितार था, जो उनके जीवन का सबसे प्रिय साथी था। हर रात्रि वे उसी पर मधुर स्वर छेड़तीं और अपने प्रभु को सुनातीं—अपने सुख, अपने दुःख, अपनी व्यथा और अपनी भक्ति की कहानी।

एक रात जब आकाश में पूर्णिमा का चंद्रमा चमक रहा था, मीरा उसी मंदिर में बैठीं, जहां वे अक्सर भजन गाती थीं। चारों ओर शांति थी, केवल घंटियों की मंद ध्वनि और दीपों की झिलमिलाहट। भक्तों की भीड़ धीरे-धीरे एकत्र हो चुकी थी। मीरा ने आंखें बंद कीं और अपने सितार के तारों को हल्के से छेड़ा—"मेरे तो गिरधर गोपाल, दूसरो न कोई" स्वर जैसे ही मंदिर की दीवारों से टकराया, वातावरण भक्ति से भर गया।

किंतु अचानक एक क्षण आया जब उनके सितार का तार टूट गया। स्वर थम गया, ताल बिखर गई, और सभा में एक हल्की हंसी की लहर दौड़ गई। कुछ लोग बोले—"अब कैसे गाओगी मीरा? बिना वाद्य के भजन अधूरा रह जाएगा।" किसी ने कहा—"संगीत बिना साधन के अधूरा होता है, देवी। भगवान भी अब कैसे सुनेंगे तुम्हारा राग?"

मीरा ने उन सबकी ओर शांत दृष्टि से देखा। फिर मुस्कराकर टूटे सितार को अपने पास रख दिया। उन्होंने धीरे-धीरे आंखें बंद कीं, दोनों हाथ जोड़ लिए, और उनके मुख से वही स्वर पुनः फूटा—"मेरे तो गिरधर गोपाल, दूसरो न कोई" पर इस बार वह स्वर पहले से भी गहरा था। उसमें न कोई तार था, न ताल, न लय—फिर भी वह सीधा हृदय को चीरकर भीतर उतर गया। ऐसा लगा जैसे स्वयं बृजधाम का मुरलीधर उस मंदिर में प्रकट होकर मीरा के साथ गा रहा हो। उनकी आंखों से अश्रु बह रहे थे, और हर आंसू मानो एक नई लय बन रहा था। पूरा मंदिर उस भक्ति के संगीत में डूब गया। भजन समाप्त हुआ। सभी लोग कुछ क्षणों तक स्तब्ध खड़े रहे। कोई कुछ कह नहीं सका। तब मीरा ने धीरे से कहा—

"संगीत बाहरी नहीं होता, वह भीतर के हृदय से उपजता है। जब आत्मा प्रभु से जुड़ जाती है, तब टूटे हुए तार भी अमृत बन जाते हैं। साधन टूट जाएं तो क्या हुआ? अगर मन जुड़ा है, तो भक्ति कभी नहीं टूटती। जिस दिन हृदय कृष्ण का मंदिर बन जाए, उस दिन हर स्वर स्वयं बजने लगता है।"

उनकी वाणी में ऐसा सत्य था कि सुनने वाले भक्त रो पड़े। कहते हैं उसी क्षण मंदिर के भीतर की एक घंटी अपने आप बज उठी—मानो स्वयं श्रीकृष्ण उस स्वर का उत्तर दे रहे हों। और जब मीरा ने अपने सितार को देखा, तो टूटा हुआ तार जैसे स्वयं जुड़ चुका था। किसी ने देखा नहीं कि वह कब जुड़ा, पर सभी ने महसूस किया कि वह मीरा की भक्ति से ही जुड़ गया था।

उस दिन से चित्तौड़ में यह कथा प्रसिद्ध हो गई कि जब भक्ति हृदय से निकलती है, तो कोई वाद्य आवश्यक नहीं रहता। मीरा ने जो भजन गाया, वह केवल शब्दों में नहीं था—वह हृदय का अमर राग था, जो आज भी हर भक्त के भीतर गूंजता है। जब कोई मनुष्य प्रेम से "हरे कृष्ण" कहता है, तो उस स्वर में कहीं न कहीं मीरा के टूटे सितार की गूंज सुनाई देती है—जिसे किसी ने छेड़ा नहीं, पर जो सदा से बजता आया है, हृदय में, आत्मा में, और प्रभु के चरणों में।

नरक चतुर्दशी पर दीपदान से होता है आध्यात्मिक जागरण

दीवाली से पहले छोटी दीवाली आती है, इसे नरक चतुर्दशी और रूप चौदस भी कहा जाता है। साथ ही कार्तिक कृष्ण चतुर्दशी तिथि को नरक चतुर्दशी के नाम से भी जाना जाता है। नरक चतुर्दशी पर सुबह के मुहूर्त में अभ्यंग स्नान करने का विधान है, इस दिन स्नान व दीपदान से पाप मिटते हैं और सौभाग्य बढ़ता है तो आइए हम आपको नरक चतुर्दशी व्रत का महत्व एवं पूजा विधि के बारे में बताते हैं। दीवाली से एक दिन पहले मनाई जाने वाली नरक चतुर्दशी को हिंदू धर्म में बहुत पवित्र और शुभ तिथि माना गया है। इसे रूप चौदस या छोटी दीवाली भी कहा जाता है। हिन्दू मान्यताओं के अनुसार इस दिन भगवान श्रीकृष्ण ने नरकासुर नामक राक्षस का वध किया था और उसके बंधन में फंसी 16 हजार महिलाओं को मुक्त कराया था। इस साल नरक चतुर्दशी 19 अक्टूबर को मनाई जाएगी। इसी कारण यह दिन अंधकार पर प्रकाश और बुराई पर अच्छाई की जीत का प्रतीक माना जाता है।

हिन्दू पंचांग के अनुसार, कार्तिक माह के कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी तिथि 19 अक्टूबर 2025 को दोपहर 1 बजकर 51 मिनट से शुरू होगी और 20 अक्टूबर 2025 को दोपहर 3 बजकर 44 मिनट तक रहेगी। इस आधार पर नरक चतुर्दशी का पर्व 19 अक्टूबर (रविवार) को मनाया जाएगा, जबकि अभ्यंग स्नान का शुभ मुहूर्त 20 अक्टूबर (सोमवार) की सुबह रहेगा।

धार्मिक मान्यताओं के अनुसार नरक चतुर्दशी पर स्नान करने से सभी पाप मिट जाते हैं और शरीर व मन शुद्ध होते हैं। इस दिन यमराज के लिए दीपदान करना बहुत शुभ माना जाता है। शाम के समय 14 दीए जलाने की परंपरा है। इनमें से एक सरसों के तेल का दीपक यमराज के नाम से जलाया जाता है, जबकि बाकी 13 दीपक घी के होते हैं। इससे अकाल मृत्यु का भय समाप्त होता है। नरक चतुर्दशी पर भगवान श्रीकृष्ण की पूजा करने से जीवन में सुख, समृद्धि और मानसिक शांति आती है। यह दिन न केवल शारीरिक शुद्धि का प्रतीक है बल्कि आध्यात्मिक जागरण का भी अवसर देता है।

नरक चतुर्दशी को पूरे दिन सर्वार्थ सिद्धि योग बना हुआ है। सर्वार्थ सिद्धि योग में किए गए कार्य सफल होते हैं और यह एक शुभ योग है। नरक चतुर्दशी पर अमृत सिद्धि योग शाम को 5 बजकर 49 मिनट से अगले दिन 20 अक्टूबर को सुबह 06 बजकर 25 मिनट तक है। उस दिन इंद्र योग भी प्रातःकाल से लेकर देर रात 02:05 ए एम तक है। उत्तराफाल्गुनी नक्षत्र प्रातःकाल से लेकर शाम 05 बजकर 49 मिनट तक है, उसके बाद से हस्त नक्षत्र है। पंडितों के अनुसार नरक चतुर्दशी की रात मिट्टी का चौमुखी दीपक जलाना अत्यंत शुभ माना गया है। इसमें सरसों का तेल डालकर चार दिशाओं की ओर चार बत्तियां लगाई जाती हैं। इस दीपक को 'यम दीप' कहा जाता है, जो मृत्यु के देवता यमराज को समर्पित होता है। इसे घर के मुख्य द्वार के बाहर दक्षिण दिशा की ओर रखकर जलाया जाता है।

"मृत्युना पाशदण्डाभ्यां कालेन च मया सह, या त्रयोदश्यां दीपदानात् सूर्यजः प्रीयतामिति॥"

धार्मिक मान्यताओं के अनुसार घर के सबसे वरिष्ठ सदस्य को यह दीपक जलाना चाहिए और जलाने के बाद दीपक को पलटकर नहीं देखना चाहिए। उस उपाय से अकाल मृत्यु का भय समाप्त होता है और घर में सुख-शांति का वातावरण बना रहता है।

नरक चतुर्दशी को काली चौदस भी कहा जाता है। इस दिन मां काली की पूजा करने से व्यक्ति को नकारात्मक ऊर्जा, भय और संकटों से मुक्ति मिलती है। पूजा के समय लाल गुड़हल के फूल अर्पित करें और "ॐ क्रीं कालिकायै नमः" मंत्र का जप करें। यह साधना शत्रु नाश और सकारात्मक ऊर्जा प्राप्ति का माध्यम मानी जाती है।

नरक चतुर्दशी पर करें ये अचूक उपाय

1. दीपक- एक मिट्टी का चौमुखी दीपक लें। इसमें सरसों का तेल भरें और चार अलग-अलग दिशाओं की ओर मुख करके चार बत्तियां लगाएं।

2. सही समय पर जलाएं दीपक - यह दीपक शाम या रात के समय जलाया जाता है, जब घर के सभी सदस्य भोजन करके सोने की तैयारी कर रहे हों।

3.दीपदान की दिशा का भी है महत्व- दीपक को घर के बाहर मुख्य द्वार के पास दक्षिण दिशा की ओर मुख करके रखें। दक्षिण दिशा यमराज की मानी जाती है।

4.करें ये काम, मिलेगा लाभ- यह 'यम दीपक' घर का सबसे बड़ा सदस्य ही जलाता है। दीपक को रखने के बाद उसे पलटकर नहीं देखना चाहिए और घर के अंदर के सदस्यों को बाहर आकर उसे देखना नहीं चाहिए।

भगवान राम के प्रिय भक्त हनुमान जी को तो हर कोई जानता है। जब हनुमान सिर्फ एक शिशु थे, तो उन्होंने सूर्य को देखा और इसे एक अद्भुत फल समझकर इसे निगल लिया, जिससे पूरी दुनिया घोर अंधकार में डूब गई। काली चौदस के दिन सभी देवी-देवताओं ने हनुमान से सूर्य को मुक्त करने के लिए विनती की, लेकिन हनुमान नहीं माने, इसलिए भगवान इंद्र ने अपने वज्र से उन पर प्रहार किया, जो हनुमान के मुंह पर लगा और सूर्य निकल आया और फिर वहां दुनिया में फिर से प्रकाश था।

एक अन्य कथा के अनुसार राजा बलि सबसे उदार राजाओं में से एक थे और उन्होंने इसके लिए बहुत प्रसिद्धि प्राप्त की, लेकिन प्रसिद्धि उनके सिर चढ़ गई और वह बहुत अहंकारी हो गए। उसने अपने पास भिक्षा के लिए आने वाले लोगों का अपमान और अपमान करना शुरू कर दिया, इसलिए भगवान विष्णु ने उसे सबक सिखाने का फैसला किया और वामन अवतार में एक बौने के रूप में आए। जब बलि ने उससे कहा कि वह जो चाहे मांग ले तो भगवान वामन ने उसके तीन पग के बराबर भूमि मांगी। यहोवा ने पहले पग से सारी पृथ्वी को, और दूसरे पग से सारे आकाश को नाप लिया। फिर उसने बाली से पूछा कि वह अपना तीसरा कदम कहां रखे।

अभियान

धन्वंतरि जयंतिः अमृत के अवतार से आरोग्य की अनंत गाथा

जब धरती पर अधर्म का अंधकार बढ़ने लगता है, जब मनुष्य लोभ में इतना डूब जाता है कि अपने शरीर और आत्मा दोनों की सुध खो बैठता है, तब ब्रह्मांड के संतुलन को बचाने कोई न कोई दिव्य शक्ति अवश्य अवतरित होती है। ऐसी ही एक अद्भुत और कल्याणकारी शक्ति हैं भगवान धन्वंतरि — जिनके नाम के उच्चारण मात्र से रोग मिटते हैं और आरोग्य की ज्योति प्रज्वलित होती है। उनका नाम स्वयं में "धन" और "तन" दोनों का संगम है — धन्वंतरि, अर्थात् वह जो शरीर को अमृतमय बना दे।

कहते हैं, जब सृष्टि के प्रारंभिक युगों में देवता और दानव अमरत्व के लिए प्रयासरत हुए, तब उन्होंने समुद्र मंथन का निर्णय लिया। यह मंथन केवल रत्नों का नहीं, बल्कि सम्पूर्ण ब्रह्मांड की शक्तियों का था। मंदराचल पर्वत मथनी बना, वासुकि नाग रस्सी बने, और स्वयं भगवान विष्णु ने कूर्म अवतार लेकर उस पर्वत को अपने पृष्ठ पर धारण किया। जब मंथन आरंभ हुआ तो पहले विष निकला — हलाहल, जो सम्पूर्ण लोकों को भस्म कर सकता था। तब भगवान शिव ने उस विष को अपने कंठ में धारण किया और नीलेकंठ कहलाए। इसी विष की उष्णता से जब त्रिलोकी व्याकुल होने लगी, तभी समुद्र से दिव्य प्रकाश प्रकट हुआ — वह थे भगवान धन्वंतरि, चतुर्भुज, पीताम्बरधारी, कमलवर्ण, जिनके हाथों में शंख, चक्र, औषधि और अमृत कलश थे। उनके प्रकट होते ही ब्रह्मांड में एक अद्भुत शांति फैल गई। उनके एक हाथ में अमृत था, जो जीवन का प्रतीक है, दूसरे में औषधि थी, जो शरीर के संतुलन का प्रतीक है, तीसरे में शंख था, जो प्राणशक्ति का प्रतीक है, और चौथे में चक्र, जो रोगों के नाश का प्रतीक बना। उस क्षण ब्रह्मांड के सभी देवताओं ने उन्हें प्रणाम किया और विष्णु के अवतार के रूप में मान्यता दी।

भगवान धन्वंतरि ने तभी घोषणा की कि मनुष्य का वास्तविक धन उसका स्वास्थ्य है। उन्होंने कहा, "जब तक शरीर स्वस्थ नहीं, तब तक कोई भी साधना, कोई भी भक्ति, कोई भी समृद्धि स्थायी नहीं।" यही कारण है कि कार्तिक कृष्ण त्रयोदशी के दिन जब वे प्रकट हुए, उस दिन को "धनतेरस" कहा गया — धन अर्थात् वैद्य धन्वंतरि की कृपा और तेरस अर्थात् उनकी अवतरण तिथि। इस दिन दीपावली के दो दिन पहले घरों में दीप जलाए जाते हैं, जिससे न केवल अंधकार मिटे, बल्कि रोगों और अशुभ शक्तियों का नाश भी हो। किंवदंतियों में आता है कि ब्रह्माजी ने एक बार कहा — "अयमायुः विज्ञानं ब्रह्मविद्यायाः उपांगं भवेत्।" अर्थात् आयुर्वेद स्वयं ब्रह्मविद्या का एक अंग है। ब्रह्मा ने एक सहस्त्र अध्याय और एक लाख श्लोकों का आयुर्वेद रचा, जिसे उन्होंने अश्विनी कुमारों को दिया। उन अश्विनी कुमारों ने देवेंद्र को सिखाया और इंद्र ने यह दिव्य विद्या भगवान धन्वंतरि को प्रदान की। धन्वंतरि ने इसे व्यवस्थित रूप से आठ विभागों में विभाजित किया — शल्य, शालाक्य, काय, बाल, ग्रंथि, दंशन, शाल्य और रसायन — जिन्हें आज 'अष्टांग आयुर्वेद' कहा जाता है। यही वह ज्ञान था जिसने भारत को चिकित्सा की जननी बना दिया।

द्वापर युग में यह वरदान साकार हुआ जब काशी नरेश राजा काश के पुत्र धन्व की संतान के रूप में भगवान धन्वंतरि ने पुनः जन्म लिया। उन्होंने भारद्वाज से आयुर्वेद का पुनः अध्ययन किया और विश्व के लिए उसकी प्रणाली स्थापित की। उनके शिष्य सुश्रुत ने इस विद्या को चिकित्सा के व्यावहारिक स्वरूप में ढाला। सुश्रुत ने ही प्रथम बार शल्य चिकित्सा का संस्थान स्थापित किया, जहाँ घाव, अंग प्रत्यारोपण, नाड़ी संचालन जैसी जटिल प्रक्रियाएँ सिखाई जाती थीं। इतिहास कहता है कि यह संस्थान काशी में स्थित था, जहाँ से आधुनिक चिकित्सा विज्ञान की जड़ें फूटीं।

जब भगवान शिव ने समुद्र मंथन के विष को पी लिया, तो उस विष की तीव्रता से उनका कंठ दग्ध होने लगा। तब भगवान धन्वंतरि ने ही उन्हें अमृत प्रदान किया। उस अमृत की कुछ बूंदें काशी नगरी में गिरीं, और तभी से कहा जाता है कि "काशी कभी नष्ट नहीं होती।" वह अमृत की भूमि बन गई — जहाँ मृत्यु भी जीवन का रूप धारण कर लेती है।

आज भी जब कोई मनुष्य आयुर्वेद के अनुसार जीवन जीता है, तो वह धन्वंतरि की परंपरा को आगे बढ़ाता है। रोगों से मुक्ति केवल औषधि से नहीं, बल्कि आचरण, विचार और संतुलन से मिलती है — यही आयुर्वेद का मूल मंत्र है। यही कारण है कि धनतेरस केवल व्यापारिक उत्सव नहीं, बल्कि शरीर, मन और आत्मा की त्रिवेणी का पर्व है।

इस पावन दिन पर घरों में भगवान धन्वंतरि का चित्र स्थापित कर दीपक जलाना अत्यंत शुभ माना जाता है। यह दीप आरोग्य का प्रतीक बनता है। पं. गणेश प्रसाद मिश्र सेवा न्यास ने इसी भावना से प्रेरित होकर अब तक देश-विदेश के तीस हज़ार से अधिक परिवारों को भगवान धन्वंतरि का पवित्र चित्र समर्पित किया है। यह केवल पूजा का चित्र नहीं, बल्कि एक संकल्प है — कि हर घर में आयुर्वेद की लौ जलती रहे, हर परिवार निरोग रहे, और हर हृदय में धन्वंतरि का अमृत प्रवाहित होता रहे।

धनतेरस की यह दिव्य रात्रि हमें यह स्मरण कराती है कि असली "धन" स्वर्ण या रजत नहीं, बल्कि वह स्वास्थ्य है, जो हमें जीवन में हर आनंद का रस प्रदान करता है। जो अपने शरीर और मन को संतुलित रखता है, वही सच्चा धनी है। भगवान धन्वंतरि की कृपा से ऐसा हर घर, हर हृदय और हर जीवन अमृतमय हो — यही सच्ची दीपावली है।

ॐ नमो भगवते धन्वंतरये अमृतकलशहस्ताय सर्वामयविनाशनाय त्रैलोक्यनाथाय श्रीमाहाविष्णवे नमः।

RNI No. GJHIN/25/A2786 Printed, Published & Owned by RAGINI JIGNESHKUMAR VAGHELA and Printed By (1) JIGNESH RASHIKBHAI GAJJAR at Vansh Corporation, A/8, Shayona Golden Estate, Shahibag, Ahmedabad - 380 004
(2) DESAI RAHUL MAHESHBHAI at Bhavani Offset, Bhatiya Ni Wadi, Opp Kalupur Railway Station, Kalupur, Ahmedabad-380 002. (3) HADIK MAHESHBHAI DESAI at Bhoomi Offset, Bhatiya Ni Wadi, Opp Kalupur Railway Station, Kalupur, Ahmedabad-380 002
and Published from B/13, Sneh Plaza Shopping Center, I.O.C. Road, Chandkheda, Ahmedabad - 382 424. Editor : JIGNESHKUMAR PATHABHAI VAGHELA

फियो ने भारतीय निर्यातकों की अंतर्राष्ट्रीय खरीद के अवसरों तक पहुँच बढ़ाने के लिए वैश्विक निविदा सेवाएँ (जीटीएस) शुरू की

(जीएनएस)। नई दिल्ली, 18 अक्टूबर, 2025: फेडरेशन ऑफ इंडियन एक्सपोर्ट ऑर्गनाइजेशन (फियो) धनतेरस के पावन अवसर पर गर्व से अपनी नवीनतम प्रमुख पहल - वैश्विक निविदा सेवाएँ (जीटीएस) का अनावरण कर रहा है - यह एक परिवर्तनकारी कदम है जिसका उद्देश्य भारतीय निर्यातकों, विशेष रूप से एमएसएमई की वैश्विक उपस्थिति का विस्तार करना है। फियो द्वारा विकसित और प्रबंधित, जीटीएस अब भारतीय व्यापार पोर्टल पर उपलब्ध है, जो व्यापार संबंधी जानकारी और सुविधा के लिए भारत का वन-स्टॉप प्लेटफ़ॉर्म है।

जीटीएस एक सदस्यता-आधारित, रीयल-टाइम निविदा एकत्रीकरण प्लेटफ़ॉर्म है जो भारतीय व्यवसायों को प्रतिदिन 15,000 से अधिक लाइव अंतर्राष्ट्रीय निविदाओं तक पहुँच प्रदान करता है, जो 150 से अधिक देशों के 8,000 से अधिक सत्यापित चैनलों से प्राप्त होती हैं। प्रमुख विकास बैंकों से लेकर सरकारी एजेंसियों, पीपीपी निकायों, बहुपक्षीय संस्थानों और वैश्विक निगमों तक, जीटीएस भारतीय निर्यातकों को उन खरीद अवसरों से सीधे जोड़ता है जो पहले बिखरे हुए, अस्पष्ट या पहुँच से बाहर थे।

जीटीएस उच्च-अवसर वाले क्षेत्रों की एक विस्तृत श्रृंखला में फैला हुआ है - जिसमें बुनियादी ढाँचा, आईटी, फार्मास्यूटिकल्स, स्वास्थ्य सेवा, रक्षा, नवीकरणीय ऊर्जा, कृषि, खाद्य उत्पाद, परामर्श, वित्त, आदि शामिल हैं। यह सुनिश्चित करते हुए कि निर्यातकों को केवल विश्वसनीय और कार्रवाई योग्य लीड प्राप्त हों, यह विश्व बैंक, एडीबी, यूनिसेफ, यूएसएआईडी जैसी प्रतिष्ठित संस्थाओं और वैश्विक स्तर पर विभिन्न राष्ट्रीय और उप-राष्ट्रीय खरीद निकायों से अवसर प्राप्त करता है। स्मार्ट फ़िल्टर, क्षेत्र और क्षेत्र-विशिष्ट डैशबोर्ड और एआई-संचालित खोज क्षमताओं के साथ, जीटीएस उपयोगकर्ताओं को वैश्विक निविदा अवसरों को तेज़ी और सटीकता के साथ ट्रैक करने, शॉर्टलिस्ट करने और उन पर कार्रवाई करने में सक्षम बनाता है। इसे न केवल जानकारी देने के लिए, बल्कि वैश्विक बोली की लागत और जटिलता को कम करने और सफलता दर में उल्लेखनीय सुधार करने के लिए और सशक्त बनाने के लिए भी डिज़ाइन किया गया है।

जीटीएस का शुभारंभ विशेष महत्व रखता है क्योंकि भारत , विशेष रूप से भारत-ब्रिटेन के व्यापक आर्थिक और व्यापार समझौते (सीईटीए) के तहत, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार वार्ताओं में अपनी भागीदारी को गहरा कर रहा है। पहली बार, भारत ने अपने सरकारी खरीद क्षेत्र को एक द्विपक्षीय व्यापार समझौते के तहत खोला है - यह एक बड़ा नीतिगत बदलाव है जो भारतीय व्यवसायों को ब्रिटेन सरकार के खरीद अवसरों तक पारस्परिक पहुँच भी प्रदान करता है। इस विकसित होते परिदृश्य में, जीटीएस एक डिजिटल सेवा से कहीं अधिक है - यह एक रणनीतिक उपकरण बन गया है। जैसे-जैसे भारत अन्य व्यापार भागीदारों के साथ समान प्रावधानों पर बातचीत करता है, भारतीय निर्यातकों को विदेशी खरीद प्रणालियों में मजबूत, वास्तविक समय की दृश्यता की आवश्यकता होगी। जीटीएस उन्हें वैश्विक स्तर पर उभरती सरकारी निविदाओं का लाभ उठाने, जटिल बोली इकोसिस्टम को नेविगेट करने और विकसित हो रही व्यापार प्रतिबद्धताओं के साथ तालमेल बिठाने में सक्षम बनाता है।

फियो के महानिदेशक एवं सीईओ डॉ अजय सहाय ने इस लॉन्च पर टिप्पणी करते हुए कहा: "धनतेरस पर जीटीएस का शुभारंभ नई शुरुआत और समृद्धि का प्रतीक है। यह केवल एक मंच नहीं है – यह भारतीय निर्यातकों के लिए दुनिया का प्रवेश द्वार है। वैश्विक निविदाओं तक पहुँच को खोलकर, जीटीएस हमारे व्यवसायों को अंतरराष्ट्रीय स्तर पर तेजी, आत्मविश्वास और सटीकता के साथ प्रतिस्पर्धा करने में सक्षम बनाता है। यह डिजिटल, डेटा-संचालित युग के लिए भारत की निर्यात रणनीति को नया रूप देने में एक महत्वपूर्ण कदम है।"

फियो सभी क्षेत्रों के निर्यातकों को https://tenders.indiantradeportal.in पर निःशुल्क परीक्षण के लिए साइन अप करके जीटीएस की शक्ति का अनुभव करने के लिए आमंत्रित करता है।

यह पहल भारतीय निर्यातकों को डिजिटल रूप से सशक्त बनाने, उनकी वैश्विक प्रतिस्पर्धात्मकता को बढ़ाने और उन्हें तेजी से परस्पर जुड़ी वैश्विक अर्थव्यवस्था में अवसरों का लाभ उठाने में मदद करने के फियो के निरंतर मिशन को मजबूत करती है।

हाथरस: लिव इन रिलेशनशिप में महिला की हत्या करने वाले को उम्रकैद की सजा

(जीएनएस)। हाथरस। हाथरस की अपर सत्र न्यायाधीश हर्ष अग्रवाल ने लिव इन रिलेशनशिप में रह रही महिला की हत्या के मामले में आरोपी प्रदीप शर्मा को दोषी ठहराते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनाई। इसके अलावा अदालत ने आरोपी पर 55 हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया, जिसे न चुकाने की स्थिति में अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा।

मामले के अनुसार, 35 वर्षीय महिला अपने पति से अलग होकर नानी के घर रह रही थी। इसी दौरान उसकी जान-पहचान गांव दयानतपुर निवासी प्रदीप शर्मा से हुई और दोनों लगभग तीन वर्षों तक पति-पत्नी की तरह साथ रहे। प्रदीप ने महिला से वादा किया था कि वह उसके बच्चों की पढ़ाई और शादी की जिम्मेदारी उठाएगा।

घटना 4 सितंबर 2021 की शाम हुई। महिला घर नहीं थी, तब प्रदीप ने उसे फोन कर गाली-गलौज और जान से मारने की धमकी दी। रात को वह महिला को अपने घर ले गया और अगले दिन सुबह 7:30 बजे उसे गोली मार दी। गंभीर हालत में महिला को बागला अस्पताल ले जाया गया, जहां से अलीगढ़ रेफर किया गया, लेकिन रास्ते में उसकी मौत हो गई।

पुलिस ने महिला की बेटी की शिकायत पर आरोपी के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया और विवेचना के बाद न्यायालय में आरोपपत्र दायर किया। पूरे मामले की सुनवाई के बाद अदालत ने प्रदीप शर्मा को दोषी करार देते हुए आजीवन कारावास और अर्थदंड की सजा सुनाई। यह सजा इस बात का संदेश भी है कि लिव इन रिलेशनशिप या किसी भी व्यक्तिगत विवाद में हिंसा और हत्या को कानून कभी नहीं बर्दाश्त करेगा।

अहमदाबाद स्टेशन पर भारी भीड़ प्रबंधन में अहमदाबाद मंडल की सफल तैयारी

(जीएनएस)। अहमदाबाद के स्थानीय उद्योगों द्वारा बोनस वितरण के कारण अचानक उत्तर/पूर्व दिशा की ओर जाने वाले यात्रियों की संख्या में भारी वृद्धि देखी गई। अहमदाबाद रेलवे स्टेशन पर लगभग 20,000 अतिरिक्त यात्रियों की भीड़ उमड़ पड़ी। इस अप्रत्याशित चुनौती का पश्चिम रेलवे के अहमदाबाद मंडल ने कुशलतापूर्वक सामना किया और एक सुव्यवस्थित तथा सुरक्षित भीड़ प्रबंधन योजना का सफलतापूर्वक क्रियान्वयन किया।

यात्रियों की सुगम आवाजाही के लिए लगभग 1.5 किलोमीटर लंबा एकदिशीय मार्ग (Unidirectional route) तैयार किया गया और स्टेशन परिसर में एक बड़ा होल्डिंग एरिया विकसित किया गया। पूर्व दिशा की ओर जाने वाली सभी ट्रेनों का संचालन विशेष रूप से प्लेटफॉर्म नंबर 8 से किया गया, जिससे भीड़ को नियंत्रित तरीके से प्रवेश और निर्गमन का अवसर मिला।

ट्रेन-वार भीड़ प्रबंधन:

- जनसाधारण एक्सप्रेस: लगभग 6,000 यात्री
- पटना के लिए विशेष ट्रेन: लगभग 6,000 यात्री
- अहमदाबाद–दरभंगा एक्सप्रेस: लगभग 3,000 यात्री
- अहमदाबाद–बरौनी एक्सप्रेस: लगभग 2,000 यात्री
- अहमदाबाद–हावड़ा एक्सप्रेस: शेष लगभग 2,000–3,000 यात्रियों को समायोजित किया गया

यात्रियों की सुविधा हेतु स्टेशन पर पेयजल की व्यवस्था, सार्वजनिक उद्घोषणा प्रणाली, प्राथमिक चिकित्सा सहायता और विशेष भीड़ नियंत्रण दल तैनात किए गए। इस पूरे अभियान में राज्य रिजर्व पुलिस (SRP) के 200 सदस्यीय बल का विशेष योगदान रहा। साथ ही, अहमदाबाद के पुलिस आयुक्त एवं रेलवे के अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक (ADG) द्वारा त्वरित सहयोग प्रदान किया गया।

स्थानीय राज्य पुलिस, रेलवे सुरक्षा बल (RPF) और सभी शाखा अधिकारियों (BOs) की सक्रिय भागीदारी के चलते यह संपूर्ण संचालन बिना किसी अप्रिय घटना के सफलता पूर्वक संपन्न हुआ। यह उदाहरण दर्शाता है कि पश्चिम रेलवे का अहमदाबाद मंडल यात्रियों की सुरक्षा, सुविधा और कुशल संचालन के लिए हमेशा तत्पर और सक्षम है।

आरक्षण पर कोर्ट के आदेश से उबल उठा तेलंगाना: बंद से ठप पड़ा जनजीवन, प्रदर्शन और तोड़फोड़ से तनाव का माहौल

हैदराबाद। तेलंगाना में शनिवार को आरक्षण को लेकर मचा राजनीतिक और सामाजिक उबाल पूरे राज्य में साफ नजर आया। उच्च न्यायालय द्वारा स्थानीय निकाय चुनावों में पिछड़े वर्ग (ओबीसी) को 42 प्रतिशत आरक्षण देने वाले सरकारी आदेश पर लगाई गई रोक के खिलाफ राज्य में भारी बंद का आयोजन किया गया, जिसने पूरे तेलंगाना को थामकर रख दिया। सड़कों पर सन्नाटा, बाजारों के शटर गिरे हुए और सार्वजनिक परिवहन ठप — यही नज़ारा शनिवार को राज्यभर में देखने को मिला। यह बंद तेलंगाना पिछड़ा वर्ग संयुक्त कार्रवाई समिति (बीसी जेएसी) की ओर से बुलाया गया था, जिसे लगभग सभी प्रमुख राजनीतिक दलों — कांग्रेस, बीआरएस और भाजपा — ने समर्थन दिया। यह पहली बार था जब सत्ता और विपक्ष दोनों एक मुद्दे पर एकजुट दिखाई दिए। प्रदेश के कई मंत्रियों ने भी खुले तौर पर बंद का समर्थन किया और कुछ तो प्रदर्शन में सड़कों पर उतर आए। हैदराबाद, निजामाबाद, करीमनगर, वारंगल और खम्मम जैसे प्रमुख शहरों में बंद का असर सबसे ज्यादा दिखा। कई जगहों पर प्रदर्शनकारियों ने नारेबाजी की, जबकि कुछ इलाकों में स्थिति तनावपूर्ण भी हो गई। कुछ कार्यकर्ताओं ने हैदराबाद के बाहरी इलाके में एक पेट्रोल पंप और एक दुकान पर तोड़फोड़ की, जिससे स्थानीय पुलिस को अतिरिक्त बल तैनात करना पड़ा। तेलंगाना स्टेट रोड ट्रांसपोर्ट कॉरपोरेशन (टीएसआरटीसी) की बस सेवाओं पर भी इस बंद का गहरा असर पड़ा। हजारों बसें डिपो में खड़ी रहीं और यात्रियों को घंटों सड़क किनारे इंतजार करते देखा गया। दिवाली के अवसर पर यात्रा कर रहे लोगों को सबसे ज्यादा दिक्कतों का सामना करना पड़ा। रेलवे स्टेशन और बस स्टैंड पर यात्रियों की भीड़ उमड़ आई, लेकिन परिवहन व्यवस्था लगभग ठप रही।

बंद के दौरान अधिकांश स्कूल, कॉलेज, व्यापारिक प्रतिष्ठान, दुकानें और बाजार पूरी तरह बंद रहे। केवल अस्पताल, एंबुलेंस सेवा और दवा दुकानें जैसी आपात सेवाएं सामान्य रहीं। कई जिलों में पुलिस ने एहतियातन धारा 144 लागू कर दी और संवेदनशील इलाकों में पुलिस गश्त बढ़ा दी गई। तेलंगाना उच्च न्यायालय ने 9 अक्टूबर को एक अंतरिम आदेश जारी करते हुए राज्य सरकार के उस फैसले पर रोक लगा दी थी, जिसके तहत स्थानीय निकाय चुनावों में ओबीसी समुदाय को 42 प्रतिशत आरक्षण दिया जाना था। कोर्ट ने कहा था कि यह सीमा संविधान द्वारा निर्धारित 50 प्रतिशत के आरक्षण कैप से अधिक है, इसलिए इस पर तत्काल रोक लगाई जाती है।

इंडिगो ने एयरबस के साथ 30 नए A350 विमानों की खरीद को दी मंजूरी, वाइड बॉडी फ्लीट का विस्तार

(जीएनएस)। नई दिल्ली। देश की सबसे बड़ी एयरलाइन इंडिगो ने अपनी वाइड बॉडी फ्लीट को दोगुना करने की दिशा में बड़ा कदम उठाया है। कंपनी ने यूरोपीय विमान निर्माता एयरबस के साथ 30 और एयरबस A350 900 विमानों की खरीद का समझौता किया है। इस डील से इंडिगो की अंतरराष्ट्रीय उड़ानों में मौजूदगी और क्षमता बढ़ेगी। इन विमानों की डिलीवरी साल 2027 से शुरू होगी और इस डील के बाद कंपनी की कुल वाइड बॉडी ऑर्डर बुक 60 विमान तक पहुंच गई है। 30 नए A350 900 विमानों का ऑर्डर इंडिगो ने पहले जून 2025 में एयरबस के साथ MOU साइन किया था, जिसे अब पक्के ऑर्डर में बदल दिया गया है। इससे पहले अप्रैल 2024 में एयरलाइन ने 30 A350 900 विमानों का शुरुआती ऑर्डर दिया था। फिलहाल, कंपनी के पास भविष्य में उपयोग के लिए 40 और वाइड बॉडी विमान खरीदने के अधिकार बचे हैं।

इन नए विमानों को ट्रेंट XWB 84 इंजन से लैस किया जाएगा, जिसके लिए इंडिगो ने रोल्स रॉयस के साथ समझौता किया है। यह इंजन लंबी दूरी की उड़ानों के लिए बेहतर फ्यूल एफिशिएंसी और प्रदर्शन प्रदान करेगा, जिससे इंडिगो को इंटरनेशनल ऑपरेशन में मजबूत स्थिति बनाने में मदद मिलेगी। इंडिगो तेजी से अपनी अंतरराष्ट्रीय मौजूदगी बढ़ा रही है। हाल ही में एयरलाइन ने मैनचेस्टर और एम्स्टर्डम के लिए उड़ानें शुरू की हैं। इसके बाद कोपेनहेगन, लंदन और एथेंस के लिए भी फ्लाइट शुरू की गई हैं। इन रूट्स के लिए कंपनी अस्थायी तौर पर डैम्प लीज पर लिए गए बोइंग 787 9 और जल्द आने वाले एयरबस A321XLR का उपयोग कर रही है।

रेल मंत्रालय ने देवगढ़ मदारिया – मारवाड़ जंक्शन ब्रॉड गेज रेल लाइन के लिए फाइनल लोकेशन सर्वे को दी मंजूरी

(जीएनएस)। रेल मंत्रालय ने देवगढ़ मदारिया से मारवाड़ जंक्शन तक 72 किलोमीटर लंबी नई ब्रॉड गेज रेल लाइन के फाइनल लोकेशन सर्वे (FLS) को मंजूरी दे दी है। स्वीकृति पश्चात यह नई रेल लाइन परियोजना जोधपुर और बीकानेर से होकर चित्तौड़गढ़ और उदयपुर तक सीधी कनेक्टिविटी प्रदान करेगी, जिससे यात्रा का समय और दूरी दोनों कम होंगे। यह नई ब्रॉड गेज रेल लिंक राजसमंद, उदयपुर और पाली जिलों में यात्रा समय को काफी कम करेगी और यात्री व माल ट्रेनों की क्षमता को बेहतर बनाएगी, इससे इन क्षेत्रों के उन हिस्सों तक भी आधुनिक रेल सुविधाएं पहुँचेंगी जहाँ अब तक यह सुविधाएं सीमित थीं। इसके माध्यम से, देवगढ़ मदारिया के किसानों की फसलें, जैसे फल और सब्जियाँ, मारवाड़ क्षेत्र के नए बाजारों तक पहुँच सकेंगी। यह लाइन मारवाड़ क्षेत्र में तेज ट्रेनों के संचालन का मार्ग सुनिश्चित करेगी, जिससे पहले की धीमी और संकरी लाइनें तेज और अधिक सुगम संपर्क का मार्ग बन जाएँगी। ये विकास कार्य दिल्ली–मुंबई औद्योगिक गलियारे (DMIC) के रणनीतिक लक्ष्यों के अनुरूप हैं और विशेष रूप से जोधपुर–पाली औद्योगिक क्षेत्र के लिए लाभकारी साबित होंगे, जो पश्चिमी भारत में एक उभरता हुआ निर्माण और लॉजिस्टिक्स हब है। बेहतर रेल इन्फ्रास्ट्रक्चर न केवल आपूर्ति श्रृंखलाओं को मजबूत करेगी, बल्कि निवेश आकर्षित करेगी, व्यापार का विस्तार करेगी और औद्योगिक केंद्रों को देश भर के बंदरगाहों और बाजारों से अधिक कुशलता से जोड़ेगी।

पर्यटन की दृष्टि से भी इसका बड़ा लाभ होगा। इस मार्ग से कुंभलगढ़ किला, चारभुजा मंदिर और द्वारकाधीश मंदिर (कंकरोली) जैसे प्रसिद्ध धार्मिक व ऐतिहासिक स्थलों तक रेल के माध्यम से पहुँचना और आसान हो जाएगा। इससे क्षेत्र में पर्यटकों की आवाजाही बढ़ेगी और स्थानीय व्यापार को भी प्रोत्साहन मिलेगा। साथ ही, यह क्षेत्र संगमरमर, ग्रेनाइट और सीमेंट उद्योगों के लिए भी प्रसिद्ध है, जिन्हें भारतीय रेल के मिशन 3000 एमटी के तहत माल ढुलाई क्षमता के बढ़ने से बड़ा लाभ मिलेगा। इससे कच्चे माल और पूर्ण रूप से तैयार उत्पादों की ढुलाई तेज, अधिक विश्वसनीय और किफायती हो सकेगी। जिससे औद्योगिक विकास और क्षेत्रीय अर्थव्यवस्था को नई गति मिलेगी। मंजूरी मिलने के बाद इस परियोजना के साथ-साथ , 969 करोड़ की लागत से चल रही 82 किलोमीटर लंबी नाथद्वारा–देवगढ़ मदारिया ब्रॉडगेज परिवर्तन परियोजना भी क्षेत्र में महत्वपूर्ण सामाजिक और आर्थिक लाभ लेकर आएगी। यह परियोजना भील, गरासिया और सहारिया जनजाति समुदायों के लिए शिक्षा, स्वास्थ्य सेवाओं और रोजगार के अवसरों तक पहुंच को बेहतर बनाकर उनके जीवन स्तर में सुधार करेगी।

तीन ट्रेनों का व्यारा स्टेशन पर अतिरिक्त ठहराव

(जीएनएस)। पश्चिम रेलवे द्वारा यात्रियों की सुविधा के लिए व्यारा स्टेशन पर तीन ट्रेनों का अतिरिक्त ठहराव प्रदान करने का निर्णय लिया गया है।

पश्चिम रेलवे के मुख्य जनसंपर्क अधिकारी श्री विनीत अभिषेक द्वारा जारी एक प्रेस विज्ञप्ति के अनुसार, इन ट्रेनों का विवरण निम्नानुसार है:

1. 23 अक्टूबर, 2025 को बांद्रा टर्मिनस से यात्रा प्रारंभ करने वाली ट्रेन संख्या 09029 बांद्रा टर्मिनस-रीवा एक्सप्रेस (साप्ताहिक) व्यारा स्टेशन पर रुकेगी। यह ट्रेन 09:38 बजे व्यारा स्टेशन पहुँचेगी और 09:40 बजे प्रस्थान करेगी। इसी प्रकार, 24 अक्टूबर, 2025 को रीवा से यात्रा प्रारंभ करने वाली ट्रेन संख्या 09030 रीवा-बांद्रा टर्मिनस एक्सप्रेस (साप्ताहिक) व्यारा स्टेशन पर रुकेगी। यह ट्रेन 07:41 बजे व्यारा स्टेशन पहुँचेगी और 07:43 बजे प्रस्थान करेगी।

2. 25 अक्टूबर, 2025 को उधना से यात्रा प्रारंभ करने वाली ट्रेन संख्या 09033 उधना-बरौनी एक्सप्रेस (द्वि-साप्ताहिक) व्यारा स्टेशन पर रुकेगी। यह ट्रेन 21:03 बजे व्यारा स्टेशन पहुँचेगी और 21:05 बजे प्रस्थान करेगी। इसी प्रकार, 27 अक्टूबर, 2025 को बरौनी से यात्रा प्रारंभ करने वाली ट्रेन संख्या 09034 बरौनी-उधना एक्सप्रेस (द्वि-साप्ताहिक) व्यारा स्टेशन पर रुकेगी। यह ट्रेन 17:56 बजे व्यारा स्टेशन पहुँचेगी और 17:58 बजे प्रस्थान करेगी। 3. 26 अक्टूबर, 2025 को उधना से यात्रा प्रारंभ करने वाली ट्रेन संख्या 09069 उधना–समस्तीपुर एक्सप्रेस (साप्ताहिक) शुरू होकर व्यारा स्टेशन पर रुकेगी। यह ट्रेन 21:11 बजे व्यारा स्टेशन पहुँचेगी और 21:13 बजे प्रस्थान करेगी। इसी प्रकार, 28 अक्टूबर, 2025 को समस्तीपुर से यात्रा प्रारंभ करने वाली ट्रेन संख्या 09070 समस्तीपुर–उधना एक्सप्रेस (साप्ताहिक) व्यारा स्टेशन पर रुकेगी। यह ट्रेन 12:00 बजे व्यारा स्टेशन पहुँचेगी और 12:02 बजे प्रस्थान करेगी।

ट्रेनों के ठहराव, समय और संरचना के संबंध में विस्तृत जानकारी के लिए यात्री कृपया www.enquiry.indianrail.gov.in पर जाकर अवलोकन कर सकते हैं।

साबरकांठा में दो गुटों के बीच भीषण झड़प, 30 से ज्यादा गाड़ियां जलीं, 10 लोग घायल, इलाके में तनाव

नई दिल्ली। गुजरात के साबरकांठा जिले में शुक्रवार देर रात माजरा गांव हिंसा और आगजनी की चपेट में आ गया जब दो गुटों के बीच विवाद अचानक हिंसक झड़प में बदल गया। देखते ही देखते गांव की गलियां पत्थरबाजी, तोड़फोड़ और आगजनी से दहक उठीं। घटना इतनी भयावह थी कि करीब 30 से अधिक वाहनों को आग के हवाले कर दिया गया, जबकि 10 से ज्यादा लोग गंभीर रूप से घायल हो गए।

स्थानीय सूत्रों के अनुसार, दोनों समूहों के बीच पुराना तनाव कई हफ्तों से simmer कर रहा था, जो शुक्रवार रात अचानक भड़क उठा। शुरुआत मामूली कहासुनी से हुई लेकिन कुछ ही मिनटों में हालात बेकाबू हो गए। दोनों ओर से पत्थरबाजी शुरू हो गई, और फिर कुछ उपद्रवियों ने वाहनों को आग लगा दी। आसपास के इलाकों में अफरा-तफरी मच गई और लोग अपने घरों में दुबक गए।

डीवाईएसपी अतुल पटेल ने बताया कि घटना रात करीब 10:30 बजे हुई, जब अचानक गांव में पत्थरबाजी, आगजनी और तोड़फोड़ शुरू हो गई। उन्होंने कहा, "स्थिति को नियंत्रण में लाने के लिए तत्काल पुलिस बल मौके पर भेजा गया। अब तक 20 लोगों को हिरासत में लिया गया है और 110 से अधिक लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई है।" उन्होंने यह भी कहा कि हिंसा के दौरान कई गाड़ियों और दुकानों को नुकसान पहुंचाया गया है।

पुलिस के अनुसार, दोनों समुदायों के बीच पुराना विवाद कुछ भूमि और स्थानीय धार्मिक कार्यक्रमों से जुड़ा बताया जा रहा है। बीते कुछ दिनों से तनाव के संकेत मिल रहे थे, लेकिन शुक्रवार को यह विवाद उग्र रूप ले बैठा। पुलिस का कहना है कि उन्होंने पहले भी दोनों पक्षों के बीच सुलह कराने की कोशिश की थी, लेकिन कुछ असामाजिक तत्वों ने स्थिति को फिर भड़का दिया।

जिला प्रशासन ने इलाके में शांति व्यवस्था बहाल करने के लिए भारी पुलिस बल तैनात कर दिया है। साबरकांठा के संवेदनशील इलाकों में अतिरिक्त पुलिस कंपनियां भेजी गई हैं और एहतियात के तौर पर इंटरनेट सेवाओं को भी कुछ हिस्सों में अस्थायी रूप से बंद कर दिया गया है। पुलिस की गश्त लगातार जारी है ताकि किसी तरह की नई हिंसा न भड़क सके।

घायलों को नजदीकी अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जहां उनकी हालत स्थिर बताई जा रही है। स्थानीय प्रशासन ने स्थिति पर कड़ी नजर रखी हुई है। वरिष्ठ अधिकारियों ने शनिवार सुबह गांव का दौरा किया और लोगों से शांति बनाए रखने की अपील की।

साबरकांठा जैसे शांत माने जाने वाले क्षेत्र में इस तरह की हिंसक घटना ने स्थानीय लोगों को झकझोर दिया है। कई निवासियों ने प्रशासन से दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की है। गांव के बुजुर्गों और सामाजिक नेताओं ने दोनों पक्षों से संयम बरतने और आपसी संवाद से विवाद सुलझाने की अपील की है।

फिलहाल गांव में सन्नाटा पसरा हुआ है और पुलिस के जवान हर गलियों में गश्त कर रहे हैं। अधिकारियों का कहना है कि स्थिति अब नियंत्रण में है, लेकिन इलाके में तनाव बना हुआ है। प्रशासन किसी भी अप्रिय स्थिति से निपटने के लिए पूरी तरह सतर्क है।

रेड कॉरिडोर के अंत की आहट: देश से मिट रहा माओवादी आतंक, अब सिर्फ 11 जिलों तक सीमित प्रभाव, पीएम मोदी बोले — निर्णायक दौर में पहुंची लड़ाई

नई दिल्ली। दशकों से देश के विकास और सुरक्षा के लिए चुनौती बने माओवादी आतंकवाद के खिलाफ भारत ने निर्णायक बढ़त हासिल कर ली है। गृह मंत्रालय के नवीनतम आंकड़ों के अनुसार, 2014 में जहां माओवादी हिंसा 182 जिलों तक फैली हुई थी, वहीं अक्टूबर 2025 तक यह दायरा घटकर सिर्फ 11 जिलों तक सिमट गया है। सरकार का लक्ष्य है कि 31 मार्च 2026 तक पूरा रेड कॉरिडोर — जो कभी नक्सल हिंसा का प्रतीक था — इतिहास के पन्नों में समा जाए।

प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने हाल ही में एक कार्यक्रम के दौरान कहा कि देश माओवादी आतंकवाद के खिलाफ निर्णायक दौर में प्रवेश कर चुका है। उन्होंने आत्मविश्वास के साथ कहा कि "वह दिन अब दूर नहीं जब भारत पूरी तरह से नक्सलवाद-मुक्त होगा। इस बार दिवाली सिर्फ रोशनी का नहीं, बल्कि माओवादी आतंकवाद से आज़ादी का उत्सव होगी।"

गृह मंत्रालय के अनुसार, पिछले मात्र 75 घंटों में 303 नक्सली कैडर ने आत्मसमर्पण किया है, जो पिछले कई वर्षों में सबसे बड़ी संख्या है। इन आत्मसमर्पणों ने यह स्पष्ट कर दिया है कि अब जंगलों से निकलकर आत्मसात और विकास की राह चुनने का दौर शुरू हो गया है।

पीएम मोदी ने कहा कि पिछले पांच दशकों में जिन इलाकों ने हिंसा, भय और असुरक्षा के साए में जीवन बिताया, आज वे विकास और आत्मनिर्भरता के रास्ते पर आगे बढ़ रहे हैं। उन्होंने कहा कि "पहले इन जिलों की पहचान गोलियों, बारूदी सुरंगों और खून-खराबे से होती थी, लेकिन आज वही

इलाके सड़कों, स्कूलों, अस्पतालों और उद्योगों से पहचान बना रहे हैं।"

प्रधानमंत्री ने कांग्रेस और तथाकथित "अर्बन नक्सल" नेटवर्क पर भी तीखा प्रहार किया। उन्होंने कहा कि कांग्रेस के शासनकाल में एक पूरा इकोसिस्टम नक्सलियों की विचारधारा को पोषित करता था। "ये लोग माओवादी आतंकवाद की वास्तविकता को छिपाने में लगे रहते थे, ताकि देश को सच्चाई न पता चले। जिनके हाथ और पैर नक्सल हिंसा में कटे, जिनकी आंखें खो गईं — उनकी आवाज़ को इन लोगों ने दबाकर रखा," पीएम मोदी ने कहा।

उन्होंने एक घटना का ज़िक्र करते हुए बताया कि माओवादी हिंसा के पीड़ितों में कई ग्रामीण, आदिवासी और किसान परिवार शामिल हैं, जिनके जीवन पर स्थायी घाव छोड़ दिए गए। "कुछ के पैर नहीं हैं, कुछ के हाथ नहीं, कुछ ने आंखें गंवाईं — पर उनकी पीड़ा कभी मीडिया या तथाकथित बुद्धिजीवियों ने सामने नहीं आने दी," प्रधानमंत्री ने कहा।

उन्होंने बताया कि कभी ऐसा दौर था जब देश का लगभग हर राज्य नक्सल हिंसा से प्रभावित था। "संविधान तो पूरे देश में लागू था, लेकिन रेड कॉरिडोर में संविधान का कोई अस्तित्व नहीं था। शाम ढलते ही लोग घर से बाहर निकलने से डरते थे, पुलिस और प्रशासन भी सुरक्षा घेरे में चलता था। हजारों लोगों की जान गई, सैकड़ों सुरक्षाकर्मी शहीद हुए, और अनगिनत परिवार उजड़ गए," उन्होंने कहा। प्रधानमंत्री ने यह भी कहा कि आज देश ने एक नई दिशा तय की है। "अब जंगलों में बंदूक की जगह विकास की योजनाएं पहुंच रही हैं। जहां पहले खदानें नक्सलियों की आय का जरिया थीं, वहीं अब वहां उद्योग और रोजगार के अवसर बन रहे हैं। स्कूलों की घंटियां अब गोली की आवाज़ को पीछे छोड़ चुकी हैं," उन्होंने कहा।

गृह मंत्रालय के अनुसार, पिछले दस वर्षों में नक्सल प्रभावित इलाकों में हिंसक घटनाओं में 85% तक की गिरावट आई है, जबकि मारे गए सुरक्षा बलों और नागरिकों की संख्या न्यूनतम स्तर पर है। सरकार की समर्पण नीति, पुनर्वास कार्यक्रम और सड़क व डिजिटल कनेक्टिविटी पर फोकस ने इस परिवर्तन को संभव बनाया है। आज जब रेड कॉरिडोर का नाम धीरे-धीरे नक्शे से मिटता जा रहा है, तो यह न केवल सुरक्षा बलों की सफलता है, बल्कि उन लाखों ग्रामीणों की भी जीत है जिन्होंने आतंक के खिलाफ विकास का साथ चुना। प्रधानमंत्री ने कहा, "माओवादी आतंकवाद के खिलाफ हमारी यह निर्णायक जीत, भारत की आत्मा की जीत है — एक ऐसी आत्मा जो हमेशा शांति, विकास और संविधान के मार्ग पर चलती है।"

हिमंत बिस्वा सरमा का चौथा कैबिनेट विस्तार

दिसपुर। असम की राजनीति में शनिवार को एक अहम बदलाव देखने को मिला जब मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा सरमा ने अपने चौथे कैबिनेट विस्तार के तहत बोडोलैंड पीपुल्स फ्रंट (बीपीएफ) के विधायक चरण बोरो को मंत्री पद की शपथ दिलाई। राज्यपाल लक्ष्मण प्रसाद आचार्य ने राजभवन में सादे लेकिन गरिमामय समारोह में बोरो को मंत्री पद की शपथ दिलाई। इस शपथग्रहण के साथ ही बीपीएफ, जो अब तक भाजपा के नेतृत्व वाले राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन (एनडीए) का औपचारिक हिस्सा नहीं थी, सरकार में शामिल हो गई है। इसे न सिर्फ असम की सियासत में एक नया समीकरण माना जा रहा है बल्कि बोडोलैंड क्षेत्र की राजनीति में भी यह घटनाक्रम गहरी रणनीतिक अहमियत रखता है।

चरण बोरो, कोकराझार जिले से लगातार दूसरी बार विधायक चुने गए हैं और बोडोलैंड क्षेत्र में बीपीएफ के प्रभावशाली नेताओं में गिने जाते हैं। उनके मंत्री बनने से बीटीआर (बोडोलैंड टेरिटोरियल रीजन) के पांच जिलों — कोकराझार, चिरांग, उदालगुरी, बक्सा और तामुलपुर — में भाजपा गठबंधन को राजनीतिक मजबूती मिलने की उम्मीद है। हाल ही में हुए बोडोलैंड क्षेत्रीय परिषद (बीटीसी) के चुनावों में बीपीएफ ने शानदार प्रदर्शन करते हुए 40 में से 28 सीटों पर जीत हासिल की थी। इस जीत ने न केवल बीपीएफ को परिषद पर स्पष्ट बहुमत दिलाया बल्कि असम की राजनीति में उसकी bargaining power को भी मजबूत किया। राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि इस चुनाव परिणाम के बाद से ही भाजपा और बीपीएफ के बीच नजदीकियां बढ़नी तय थीं। मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा सरमा ने कहा कि "राज्य सरकार सबको साथ लेकर विकास की यात्रा को आगे बढ़ाना चाहती है। बोडोलैंड क्षेत्र असम की आत्मा का एक अभिन्न हिस्सा है और वहां के लोगों की आकांक्षाओं को पूरा करना हमारी प्राथमिकता है।"

बिहार चुनाव में रिश्तों की राजनीति: पति-पत्नी, सास-बहू और पिता-पुत्र की जोड़ियां मैदान में, परिवार के लिए पसीना बहा रहे दिग्गज नेता

मुजफ्फरपुर। बिहार विधानसभा चुनाव इस बार सिर्फ राजनीतिक लड़ाई तक सीमित नहीं है, बल्कि यह परिवारों की आपसी ताकत और रिश्तों की राजनीति का भी मंच बन गया है। इस चुनावी मैदान में पति-पत्नी, सास-बहू, बेटे-बेटी, समधन-साली तक हर कोई एक-दूसरे के लिए प्रचार और समर्थन में जुटा हुआ दिखाई दे रहा है। जहां एक तरफ पार्टी और गठबंधन की रणनीति काम कर रही है, वहीं दूसरी ओर पारिवारिक संबंधों का दबदबा भी चुनाव के स्वरूप को प्रभावित कर रहा है।

हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा (सेक्युलर) के प्रमुख और पूर्व मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी इस बार अपने पूरे परिवार को चुनावी रणभूमि में उतार रहे हैं। गयाजी के इमामगंज से मांझी की बहू दीपा मांझी, बाराचट्टी से उनकी सास और समधन ज्योति देवी और जमुई के सिकंदरा से दामाद प्रफुल्ल कुमार मांझी मैदान में हैं। खुद मांझी इन सभी के लिए जनसभाओं में वोटरों से समर्थन की अपील करेंगे। वहीं, उनके बेटे और वर्तमान राज्य सरकार में मंत्री संतोष कुमार सुमन भी पत्नी और सास के लिए प्रचार अभियान में सक्रिय हैं। इस परिवार की सक्रिय भागीदारी ने साबित कर दिया है कि राजनीतिक गठबंधन और पारिवारिक रिश्तों का संयोजन इस बार चुनावी रणनीति का अहम हिस्सा है।

दरभंगा जिले के गौड़ाबौराम में भाजपा विधायक स्वर्णा सिंह इस बार अपने पति सुजीत कुमार के लिए मैदान में उतरी हैं। पिछले पांच साल में किए गए कार्यों का हवाला देकर वे जनता से अपने पति के लिए समर्थन मांग रही हैं। इस क्षेत्र में जातीय और धार्मिक समीकरण भी चुनाव के नतीजों पर गहरा असर डालते हैं। स्वर्णा और उनके पति का यह संयुक्त अभियान यह दिखाता है कि परिवार का समर्थन चुनावी जीत के लिए कितना निर्णायक साबित हो सकता है।

सासाराम में राष्ट्रीय लोक मोर्चा के प्रमुख उपेंद्र कुशवाहा अपनी पत्नी स्नेहलता कुशवाहा के लिए प्रचार कर रहे हैं। उपेंद्र ने इस बार खुद चुनाव न लड़कर पत्नी को उम्मीदवार बनाया है और उनके बेटे दीपक कुशवाहा को भविष्य के लिए तैयार कर रहे हैं। पिता-पुत्र और पति-पत्नी की यह साझा रणनीति स्थानीय राजनीति में नए समीकरण बना रही है।

समस्तीपुर के वारिसनगर में जदयू विधायक अशोक कुमार मुन्ना अपने बेटे डॉ. मांजरीक मृणाल के लिए पसीना बहा रहे हैं। मृणाल अमेरिका से आए नवोदित राजनीतिक चेहरे हैं, और उनके लिए यह पहला चुनाव है। पिता के अनुभव और बेटे की शिक्षा तथा आधुनिक छवि का संयोजन क्षेत्र के मतदाताओं को आकर्षित कर रहा है। जहानाबाद की घोसी सीट पर भी पिता-पुत्र की जोड़ी सक्रिय है, जहां अरुण कुमार के बेटे ऋतुराज कुमार के लिए प्रचार में खुद पिता जुटे हैं।

राजद ने भी इस चुनाव में रिश्तों के कॉकटेल को मजबूती दी है। रालोजपा के पूर्व केंद्रीय संसदीय बोर्ड अध्यक्ष सूरजभान सिंह की पत्नी वीणा देवी मोकामा से उम्मीदवार हैं। सारण के परसा क्षेत्र से तेज प्रताप यादव की चचेरी साली करिश्मा यादव मैदान में हैं, जबकि तेजस्वी यादव साली के लिए प्रचार करेंगे। परिवार की यह सक्रिय भागीदारी राजद की चुनावी रणनीति में नए आयाम जोड़ रही है। सिवान जिले के रघुनाथपुर विधानसभा क्षेत्र में इस बार राजनीतिक नब्ज पर नजर रखने वालों के लिए खास दृश्य देखने को मिला। यहां राजग गठबंधन ने जदयू के विकास कुमार सिंह उर्फ जीशु सिंह को उम्मीदवार बनाया है। महागठबंधन में राजद ने दिवंगत पूर्व सांसद मो. शहाबुद्दीन के पुत्र ओसामा शहाब को मैदान में उतारा है। वहीं, जनसुराज ने राहुल कीर्ति सिंह को टिकट देकर नए चेहरे को मौका दिया है। यह सीट शहाबुद्दीन परिवार की विरासत और पारिवारिक जुड़ाव की राजनीति के लिए चर्चित है।

ओसामा शहाब ने 2024 के लोकसभा चुनाव में अपनी मां हेना शहाब के साथ निर्दलीय चुनाव लड़ा था, लेकिन सफलता नहीं मिली। अब उन्होंने राजद में पुनः प्रवेश कर लिया है और पिता की विरासत संभालने के साथ रघुनाथपुर से चुनावी मैदान में हैं। जदयू के उम्मीदवार विकास कुमार सिंह पहली बार चुनाव लड़ रहे हैं और वर्तमान सरकार के कार्यों और कल्याणकारी योजनाओं के आधार पर जनता का समर्थन जुटाने की कोशिश कर रहे हैं।

बिहार चुनाव में इस बार स्पष्ट रूप से दिख रहा है कि राजनीति केवल दल और नीतियों तक सीमित नहीं है, बल्कि परिवार और रिश्तों के असर ने चुनावी प्रक्रिया को और रोचक बना दिया है। हर पार्टी और हर उम्मीदवार अपने परिवार के सहयोग से जनता तक संदेश पहुंचा रहे हैं। इस चुनाव में यही पारिवारिक राजनीति और रिश्तों की ताकत जनता को प्रभावित करने वाला मुख्य हथियार बन रही है। पार्टी चाहे बाद में आए, लेकिन रिश्तेदारी पहले आ चुकी है, यही बिहार चुनाव का नया सच बन गया है।

नुआपड़ा उपचुनाव में पैसे का खेल भड़का, टिटिलागढ़ स्टेशन और साप्ताहिक एक्सप्रेस से 90 लाख रुपये बरामद

भुवनेश्वर। नुआपड़ा उपचुनाव की गर्माहट सिर्फ राजनीतिक मंच तक सीमित नहीं रही, बल्कि इसमें अवैध धन के खेल ने भी हड़कंप मचा दिया है। टिटिलागढ़ रेलवे स्टेशन और साप्ताहिक एक्सप्रेस से बड़ी रकम जब्त होने की खबर ने चुनावी माहौल को और गंभीर बना दिया है। रेलवे पुलिस ने टिटिलागढ़ और केसिंगा स्टेशन के बीच चल रही धरतियाबा सुपरफास्ट एक्सप्रेस में संदिग्ध गतिविधियों पर कड़ी कार्रवाई की।

जानकारी के अनुसार, आरपीएफ को सूचना मिली कि ट्रेन में अवैध तरीके से बड़ी रकम ढुलाई की जा रही है। इसके बाद आरपीएफ की विशेष टीम ने तलाशी अभियान शुरू किया। इस दौरान नीले रंग के बैग में संदिग्ध सामग्री ले जाते दो व्यक्तियों को देखा गया। जब उनका पीछा किया गया, तो दोनों ट्रेन से उतरकर भागने की कोशिश करने लगे। आरपीएफ ने उन्हें पकड़ लिया और थाने लाया। बैग की जांच करने पर उसमें 70 लाख रुपये बरामद हुए। पकड़े गए दोनों आरोपी बिहार के उमेश प्रसाद और झारखंड के प्रभात साहू हैं। दोनों कोई भी दस्तावेज नहीं दिखा सके कि यह रकम वैध है या उनके पास इसका कोई प्रमाण है।

साथ ही 'भगत की कोठी' साप्ताहिक एक्सप्रेस से भी 20 लाख रुपये जब्त किए गए हैं। रेलवे पुलिस ने तलाशी के दौरान दो अन्य व्यक्तियों को लाल बैग के साथ संदिग्ध हालत में पाया। उनकी पूछताछ के बाद आवश्यक दस्तावेज दिखाने पर उनकी राशि वापस लौटा दी गई। इस अभियान में रेलवे पुलिस अधिकारी के.एस. प्रकाश, हनुमान सिंह, शैलेन्द्र कुमार और अशोक बेहेरा शामिल थे।

राजनीतिक और सुरक्षा विशेषज्ञों के अनुसार, टिटिलागढ़ ब्लॉक नुआपड़ा जिले की सीमा के पास होने के कारण इसे उपचुनाव के दौरान अवैध धन के ले जाने का मार्ग माना जा रहा है। शुरुआती जांच में संकेत मिले हैं कि बरामद रकम उपचुनाव में इस्तेमाल की योजना के तहत लायी जा रही थी। वहीं, यह भी कहा जा रहा है कि बलांगीर जिले में चल रहे नशा कारोबार के लिए बिहार और झारखंड के व्यापारी भी इस रकम को लाकर ले जा रहे थे।

इस घटना ने न केवल चुनावी प्रक्रिया में वित्तीय अनुशासन की चिंता को बढ़ा दिया है बल्कि राजनीतिक दलों और प्रशासन दोनों के लिए गंभीर चेतावनी का संकेत भी दिया है। नुआपड़ा उपचुनाव में अवैध धन और रसूख के खेल ने यह साबित कर दिया कि चुनाव में सिर्फ वोट नहीं, पैसा भी कितना निर्णायक भूमिका निभाता है। रेलवे पुलिस और आयकर विभाग की जांच जारी है, और आने वाले दिनों में इस मामले में और खुलासे होने की संभावना है।

यह घटना नुआपड़ा उपचुनाव की निष्पक्षता और पारदर्शिता पर सवाल उठाती है, जबकि प्रशासन ने इसे लेकर कड़ा संदेश दिया है कि अवैध धन और बाहरी हस्तक्षेप को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। चुनावी प्रक्रिया में निष्पक्षता बनाए रखने के लिए अधिकारियों ने पहले ही सख्त निगरानी और अभियान चलाने की बात कही है।

बंगाल स्कूल भर्ती घोटाले में बड़ा मोड़: ईडी ने टीएमसी विधायक जीवन कृष्ण साहा के खिलाफ दायर किया 80 पृष्ठों का आरोपपत्र

कोलकाता। पश्चिम बंगाल के स्कूल नौकरी घोटाले में आज नया विकास हुआ है। प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने तृणमूल कांग्रेस (टीएमसी) के विधायक जीवन कृष्ण साहा के खिलाफ बैंकशाल अदालत में 80 पृष्ठों का आरोपपत्र दाखिल किया है। अधिकारियों ने बताया कि साहा को केंद्रीय एजेंसी ने प्रश्नपत्रों में हेरफेर और रिश्वतखोरी के आरोप में अगस्त में गिरफ्तार किया था, और अब उनकी गिरफ्तारी के लगभग 60 दिन बाद यह आरोपपत्र अदालत में पेश किया गया।

ईडी के एक वरिष्ठ अधिकारी ने 'पीटीआई-भाषा' से बातचीत में कहा, "हमने आज जीवन कृष्ण साहा के खिलाफ आरोपपत्र दाखिल किया है। इसमें स्कूल भर्ती घोटाले से जुड़े सभी अहम तथ्यों का विवरण मौजूद है। यह दस्तावेज कुल 80 पृष्ठों का है और इसमें साहा की कथित संलिप्तता का पूरा ब्यौरा शामिल है।" आरोपपत्र में कथित हेरफेर, रिश्वतखोरी और अन्य अनियमितताओं की पूरी कहानी विस्तार से दर्ज की गई है, जिससे यह मामला और गंभीर बन गया है।

अधिकारियों के अनुसार, साहा के खिलाफ कार्रवाई स्कूल भर्ती प्रक्रिया में भ्रष्टाचार और अनियमितताओं को उजागर करने के मकसद से की गई है। इस घोटाले में कई उम्मीदवारों को नौकरी देने या न देने के फैसले में कथित रूप से अनियमित तरीके अपनाए गए थे। ईडी ने पिछले कुछ महीनों में इस मामले में गहन जांच की है और अब आरोपपत्र के दाखिल होने के साथ ही न्यायिक प्रक्रिया अगले चरण में प्रवेश कर चुकी है।

साहा की गिरफ्तारी और आरोपपत्र दाखिल होने के बाद राजनीतिक हलकों में भी हलचल मची हुई है। विपक्ष और विभिन्न सामाजिक संगठन इस मामले को शिक्षा क्षेत्र में बढ़ती भ्रष्टाचार की गंभीर चेतावनी के रूप में देख रहे हैं। ईडी की कार्रवाई ने यह स्पष्ट कर दिया है कि उच्च पदों पर बैठे व्यक्ति भी कानून से ऊपर नहीं हैं और किसी भी समय जांच के दायरे में आ सकते हैं।

इस मामले की आगे की सुनवाई बैंकशाल अदालत में होने वाली है, और यह देखने की बात होगी कि अदालत किस तरह से इस मामले में आगे की कार्रवाई करती है। ईडी के अधिकारियों ने कहा कि आरोपपत्र में दर्ज सभी तथ्यों और सबूतों के आधार पर जल्द ही आगे की कानूनी कार्रवाई शुरू की जाएगी। इस घोटाले की जांच और सुनवाई पूरी तरह पारदर्शिता और नियमों के तहत की जा रही है, ताकि न्याय सुनिश्चित हो सके और स्कूल भर्ती प्रक्रिया में सुधार किया जा सके।

दीवाली-छठ में घर छोड़ने से पहले पुलिस को दें सूचना, रांची पुलिस करेगी विशेष निगरानी और गश्ती

रांची। दीवाली और छठ जैसे बड़े त्योहारों के अवसर पर जब लोग अपने परिवार के साथ घर से बाहर निकलते हैं, तब यह समय चोरों के लिए सबसे उपयुक्त माना जाता है। हर साल इन त्योहारों में चोरी की घटनाओं में वृद्धि देखी जाती है। इस बार भी रांची पुलिस ने नागरिकों से विशेष अपील की है कि वे अपने घरों को खाली करने से पहले संबंधित थाना को इसकी सूचना दें, ताकि उनके घर की सुरक्षा सुनिश्चित की जा सके।

पुलिस का कहना है कि यदि कोई परिवार त्योहारों के दौरान घर को खाली छोड़ता है और इसकी पूर्व सूचना थाने को नहीं देता, तो चोरी की संभावना बढ़ जाती है। खाली घर चोरों के लिए आसान निशाना बन जाते हैं। इसलिए पुलिस ने स्पष्ट निर्देश दिए हैं कि लोग अपने घरों के बाहर जाने की तारीख और वापसी का समय थाने को सूचित करें। इससे पुलिस संबंधित इलाके में विशेष निगरानी रख सकेगी और संदिग्ध गतिविधियों पर तुरंत कार्रवाई कर पाएगी। साथ ही, पुलिस ने नागरिकों से कहा है कि वे अपने घरों की सुरक्षा के लिए ताले मजबूत करें, खिड़कियों और दरवाजों पर अतिरिक्त सुरक्षा उपाय अपनाएं, और जहां संभव हो सीसीटीवी या अलार्म सिस्टम का उपयोग करें। पड़ोस में किसी भी संदिग्ध गतिविधि की सूचना तुरंत पुलिस को दें। यह कदम न केवल व्यक्तिगत सुरक्षा के लिए, बल्कि पूरे मोहल्ले की सुरक्षा के लिए भी महत्वपूर्ण है।

शहर में चोरी की घटनाओं में लगातार वृद्धि हुई है। पुलिस के आंकड़ों के अनुसार, पिछले पांच वर्षों में चोरी की संख्या इस प्रकार रही:

- 2021: 1902 मामले
- 2022: 2377 मामले
- 2023: 2550 मामले
- 2024: 1225 मामले
- 2025 (मई तक): 761 मामले

इन आंकड़ों से स्पष्ट होता है कि त्योहारों के दौरान चोरी की घटनाओं में तेजी आती है। रांची के सदर, बरियातू, लालपुर, सुखदेव नगर, धुर्वा, हटिया, खेलगांव और नामकुम जैसे इलाके सबसे संवेदनशील माने जा रहे हैं, जहां चोरों की सक्रियता अधिक रहती है।

पुलिस ने इस बार त्योहारों के मद्देनजर विशेष सुरक्षा रणनीति बनाई है। संवेदनशील इलाकों में गश्ती दलों की संख्या बढ़ाई जा रही है और संदिग्ध गतिविधियों पर पैनी नजर रखने के लिए विशेष टीमें गठित की गई हैं। इसके अलावा, सीसीटीवी कैमरों की मदद से लगातार निगरानी की जाएगी। पुलिस अधिकारी बताते हैं कि त्योहारों में सुरक्षा व्यवस्था को और सुदृढ़ बनाने के लिए दिन-रात गश्ती जारी रहेगी और किसी भी चोरी की घटना पर तत्काल कार्रवाई की जाएगी।

रांची पुलिस का संदेश है कि त्योहारों का आनंद सुरक्षित वातावरण में ही लिया जा सकता है। घर खाली करने से पहले सूचना देने और सुरक्षा उपाय अपनाने से नागरिक खुद को और अपने परिवार को सुरक्षित रख सकते हैं। ऐसे में पुलिस और नागरिकों के संयुक्त प्रयास से शहर में त्योहारों की खुशी में कोई व्यवधान नहीं आएगा।

केरल और तमिलनाडु में बारिश का कहर, 6 जिलों में ऑरेंज अलर्ट; बांधों से पानी छोड़े जाने के बाद राहत एवं बचाव कार्य तेज

नई दिल्ली। देश के दक्षिणी राज्यों के मौसम ने हालात और तनावपूर्ण कर दिए हैं। केरल और तमिलनाडु में मूसलाधार बारिश का असर लगातार बढ़ रहा है, जिसके कारण लोगों की ज़िंदगियों और कृषि को खतरा मंडरा रहा है। मौसम विभाग ने केरल के 6 जिलों में ऑरेंज और 8 जिलों में येलो अलर्ट जारी किया है। एर्नाकुलम, इडुक्की, मलप्पुरम, कोझिकोड, कन्नूर और कासरगोड में तेज बारिश और आंधी-तूफान, वज्रपात और मेघगर्जन की चेतावनी दी गई है।

इडुक्की जिले के नेदुमकंदम, कमिली और कट्टाप्पाना में बाढ़ का पानी कई घरों में घुस गया है। सड़कों पर जलभराव ने यात्रा और रोजमर्रा की जिंदगी को बाधित कर दिया है। स्थानीय प्रशासन ने प्रभावित लोगों को घरों से निकालकर राहत शिविरों में सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया। वहीं, मुल्लापेरियार बांध में जलस्तर तेजी से बढ़ने के कारण तमिलनाडु सरकार ने 13 गेट 100 सेंटीमीटर तक खोल दिए हैं और बांध से 1400 क्यूसेक पानी छोड़ा गया है। इसके अलावा क्षेत्र के अन्य तीन बांधों से भी पानी छोड़ा जा रहा है।

एर्नाकुलम में रेलवे स्टेशन और आसपास की सड़कें तालाब में बदल गई हैं। नदियों का जलस्तर भी बढ़ रहा है और जिले के अधिकारी नदियों के पास रहने वाले लोगों के लिए अलर्ट जारी कर चुके हैं। तेज बारिश के कारण फसलें भी बुरी तरह प्रभावित हुई हैं। मछुआरों को समुद्र से दूर रहने के निर्देश दिए गए हैं ताकि कोई अप्रिय घटना न घटे।

तमिलनाडु में भी अगले चार दिनों तक भारी बारिश का अनुमान है। बंगाल की खाड़ी में बने निम्न दबाव के क्षेत्र के कारण कोयंबटूर जिले के पहाड़ी इलाके, नीलगिरी, इरोड, तिरुप्पुर, थेनी, तेनकासी, तिरुनेलवेली और कन्नयाकुमारी में भारी से बहुत भारी बारिश होने की संभावना जताई गई है। स्थानीय प्रशासन ने लोगों को नदी और निचले इलाकों से दूर रहने की चेतावनी दी है।

मौसम विभाग ने नागरिकों से अपील की है कि वे सुरक्षित स्थानों पर रहें और अचानक बढ़ती बारिश के चलते किसी भी तरह की जोखिम भरी गतिविधि में शामिल न हों। राज्य प्रशासन ने बचाव और राहत कार्य तेज कर दिया है। पुलिस और आपदा प्रबंधन विभाग लगातार प्रभावित इलाकों में लोगों की मदद कर रहे हैं।

इस बार की बारिश ने यह भी स्पष्ट कर दिया है कि मौसम की अनिश्चितताओं के बीच सतर्कता बेहद जरूरी है। अधिकारियों ने कहा कि अगले 48 से 72 घंटे सबसे संवेदनशील होंगे, और इस दौरान कोई भी अप्रिय घटना होने की संभावना को ध्यान में रखते हुए सभी तैयारियों को दुरुस्त रखा गया है।

झारखंड में बहू की हत्या के मामले में सास को आजीवन कारावास, न्याय की जीत

देवघर। झारखंड के देवघर जिले की अदालत ने शनिवार को एक दुखद और दिल दहला देने वाले मामले में सजा सुनाई। अदालत ने 60 वर्षीय अनीता देवी को अपनी बहू कविता देवी की हत्या के जुर्म में आजीवन कारावास की सजा सुनाई और 10,000 रुपये का जुर्माना भी लगाया। इस फैसले से पीड़िता के परिवार को न्याय मिलने की उम्मीद जागी है, जबकि समाज में घरेलू हिंसा के खिलाफ सख्त संदेश भी गया है।

अदालत में सुनवाई के दौरान यह तथ्य सामने आया कि पीड़िता कविता देवी ने अपनी मृत्यु से पहले अपना बयान दर्ज कराया था। बयान के अनुसार, उसकी और सास अनीता देवी के बीच झगड़ा हुआ था। झगड़े के बाद कविता अपने घर लौट गई, जहां सूखा भूसा रखा था। कुछ ही देर में उसकी सास ने आग लगा दी, जिससे कविता की साड़ी में आग फैल गई। पीड़िता मदद के लिए चिल्लाती रही, लेकिन घर के लोग और आस-पड़ोस के लोग समय पर उसकी मदद के लिए नहीं पहुंचे। कुछ लोगों ने आग बुझाई, लेकिन तब तक कविता की हालत गंभीर हो चुकी थी और उसकी मौत हो गई।

घटना के दिन, 23 अप्रैल, 2022 को सारवां थाने में प्राथमिकी दर्ज की गई। उसके बाद पुलिस ने जांच की और दस मार्च, 2025 को आरोप-पत्र दाखिल किया गया। अदालत ने इस मामले की त्वरित सुनवाई करते हुए फैसला सुनाया और दोषी सास को कठोर सजा दी।

अदालत ने स्पष्ट किया कि घरेलू हिंसा और पारिवारिक कलह के कारण किसी भी व्यक्ति की जान लेना गंभीर अपराध है और इसे सहन नहीं किया जाएगा। अतिरिक्त सरकारी वकील अशोक कुमार राय ने बताया कि यह निर्णय न्याय की जीत है और पीड़ित परिवार को थोड़ी राहत देने वाला है।

इस सजा से यह संदेश गया है कि चाहे उम्र कितनी भी हो, किसी की जान लेने वाला कानून की पकड़ से बाहर नहीं रहेगा। साथ ही, यह मामला समाज में महिलाओं की सुरक्षा और घरेलू हिंसा के खिलाफ जागरूकता बढ़ाने की आवश्यकता को भी रेखांकित करता है।

भाई-दौज से पहले हसनपुर में 17 वर्षीय बहन की मौत, बुखार ने छीना परिवार का सबसे बड़ा सहारा

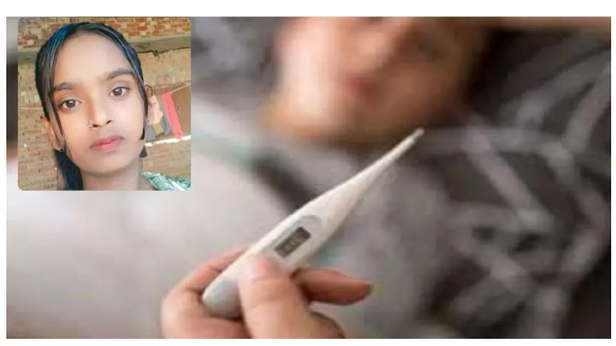

हसनपुर। दीपावली और भाई-दौज जैसे त्योहारों की खुशियों से पहले हसनपुर के एक परिवार पर दुःख का पहाड़ टूट पड़ा। दौलतपुर कला निवासी जितेंद्र प्रजापति की इकलौती बेटी, 17 वर्षीय अंशु प्रजापति, लंबी बीमारी के बाद शनिवार को रास्ते में ही दम तोड़ गई। अंशु आदर्श इंटर कॉलेज कुटी दौलतपुर में कक्षा 11 की छात्रा थी और दो भाइयों की सबसे बड़ी बहन थी।

जानकारी के अनुसार, अंशु कई दिनों से बुखार से परेशान थी। परिवार ने गांव के स्थानीय चिकित्सक से उसका इलाज करवाया। लेकिन शनिवार को उसकी हालत अचानक बिगड़ गई। परिवार ने उसे हसनपुर के एक निजी अस्पताल में भर्ती कराया। चिकित्सक ने उसकी नाजुक स्थिति को देखकर उसे मेरठ रेफर कर दिया। स्वजन उसे मेरठ ले जा रहे थे, लेकिन रास्ते में अंशु की मृत्यु हो गई। इस खबर ने पूरे परिवार और गांव में शोक की लहर दौड़ा दी।

अंशु की मौत से उसके माता-पिता और दो भाइयों का घर गमगीन हो गया। परिवार की इकलौती बेटी के खोने का दर्द किसी शब्द में बयां नहीं किया जा सकता। उसके अंतिम संस्कार की रस्में गंगा घाट पर सम्पन्न की गईं, जहां पूरे गांव के लोग भावुक होकर अंतिम दर्शन करने पहुंचे।

हसनपुर के चिकित्सा अधीक्षक डॉ. धुर्वेंद्र सिंह ने बताया कि बुखार के कारण अंशु की मृत्यु हुई, लेकिन इसके साथ ही कोई अन्य स्वास्थ्य समस्या भी रही होगी। उन्होंने परिवार को सहानुभूति देते हुए कहा कि आगे इस प्रकार की स्थिति में समय पर चिकित्सकीय सहायता लेना बेहद महत्वपूर्ण है।

अंशु की आकस्मिक मृत्यु ने यह संदेश भी दिया कि छोटे गांवों में स्वास्थ्य सुविधाओं की कमी और समय पर इलाज न मिलने के कारण युवा जीवन पर गहरा असर पड़ता है। दीपावली और भाई-दौज की खुशियों के बीच इस घटना ने पूरे इलाके में मातम का माहौल पैदा कर दिया है।

तीन नए पोतों के जलावतरण से मजबूत होगी भारतीय नौसेना, चीन पर बढ़ेगी बढ़त

कोच्चि। भारत अब नौसैनिक मोर्चे पर भी चीन को पीछे छोड़ने के लिए तैयार है। कोचीन शिपयार्ड लिमिटेड (सीएसएल) ने शनिवार को तीन अत्याधुनिक पोतों का एक साथ जलावतरण कर देश की नौसैनिक ताकत को और मजबूत करने की दिशा में बड़ी उपलब्धि हासिल की। इस ऐतिहासिक अवसर पर भारतीय नौसेना और जहाज निर्माण उद्योग की क्षमता और तकनीकी उत्कृष्टता की झलक देखने को मिली।

जलावर्तन किए गए तीन पोतों में एंटी-सबमरीन वारफेयर शैलो वाटर क्राफ्ट (एएसडब्ल्यू एसडब्ल्यूसी), हाइब्रिड इलेक्ट्रिक मेथनाल-रेडी कमीशनिंग सर्विस आपरेशन वेसल (सीएसओवी) और देश का सबसे बड़ा ट्रेलर सक्शन हापर ड्रेजर, डीसीआइ ड्रेज गोदावरी शामिल हैं। सीएसएल ने बताया कि एक साथ तीन पोतों का निर्माण और जलावतरण भारत की जहाज निर्माण क्षमता, टिकाऊ प्रौद्योगिकी और इंजीनियरिंग कौशल को उजागर करता है। यह कदम मैरीटाइम इंडिया विजन 2030 और आत्मनिर्भर भारत पहल के तहत भारत की इंजीनियरिंग उत्कृष्टता और स्वदेशीकरण की प्रतिबद्धता को भी दर्शाता है। एएसडब्ल्यू एसडब्ल्यूसी भारतीय नौसेना के लिए निर्मित आठ जहाजों की श्रृंखला का छठा पोत है। यह पोत मौजूदा अभय श्रेणी के जलपोतों की जगह लेगा और आईएनएस मगदाला के रूप में नौसेना में शामिल होने के बाद तटीय पनडुब्बी रोधी क्षमता को बढ़ाएगा। 78 मीटर लंबा यह पोत पानी के नीचे सेंसर, हल्के टारपीडो, एएसडब्ल्यू रॉकेट और बारूदी सुरंग बिछाने की विशेष क्षमता से लैस है। इसके शामिल होने से नौसेना की सुरक्षा और गहन समुद्री निगरानी में सुधार होगा। डीसीआइ ड्रेज गोदावरी भारत का सबसे बड़ा ड्रेजर है। 127 मीटर लंबा यह पोत तल तलछट को इकट्ठा करने और उसका निस्तारण करने के उद्देश्य से विकसित किया गया है। यह पोत बंदरगाह विकास, भूमि सुधार और जलमार्गों के रखरखाव में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। इसे रायल आईएचसी, नीदरलैंड के सहयोग से ड्रेजिंग कारपोरेशन ऑफ इंडिया के लिए बनाया गया है। तीसरा पोत, हाइब्रिड इलेक्ट्रिक मेथनाल-रेडी सीएसओवी, 93 मीटर लंबा है और तटीय पवन चक्कियों के निर्माण, संचालन और रखरखाव के लिए तैयार किया गया है। यह पोत हाइब्रिड प्रोपल्सन प्रणाली, मेथनाल-रेडी इंजन, बड़ी लिथियम-आयन बैटरी पैक और मोशन-कंपेंसटेड गैंगवे सिस्टम से लैस है। इसके चलते यह पोत तटीय ऊर्जा परियोजनाओं के रखरखाव में सक्षम होने के साथ-साथ तैरते होटल के रूप में भी कार्य कर सकता है। इन पोतों के जलावतरण से न केवल भारत की नौसेना की शक्ति में वृद्धि होगी, बल्कि यह देश के समुद्री सुरक्षा ढांचे को और मजबूत करेगा। विशेषज्ञों का मानना है कि इन पोतों के शामिल होने से भारतीय नौसेना चीन और अन्य पड़ोसी देशों के मुकाबले समुद्री मोर्चे पर तकनीकी और सामरिक बढ़त हासिल करेगी। यह कदम भारतीय समुद्री महत्वाकांक्षाओं और स्वदेशी रक्षा उत्पादन की दिशा में एक और बड़ा मील का पत्थर साबित होगा।